

अनुगामिनी

ज्ञानवापी के एएसआई सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर 3 मानहानि केस में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सजा पर रोक 8

पुलिस प्रशासन का उपयोग कर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है सरकार : गणेश राई

अनुगामिनी नि.सं.
गंगटोक, 04 अगस्त। सिटीजन एक्शन पार्टी सिक्किम की ओर से आज योक्सम-ताशीडिंग निर्वाचन क्षेत्र के गेरेथांग बाजार में पार्टी की निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय समिति की समन्वय बैठक आयोजित की गई। पार्टी अध्यक्ष एलपी काफ्ले की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में मुख्य समन्वयक गणेश राई के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में क्षेत्र की आम जनता उपस्थित थी। बैठक का संचालन सीएपीएस के गेजिंग जिला प्रचार अध्यक्ष खंडेन्द्र दहाल ने किया। बैठक में वक्तव्य रखते हुए पार्टी नेता गणेश राई ने राज्य की एएसकेएम सरकार की तीखी आलोचना करते हुए पुलिस-प्रशासन का उपयोग कर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया। गेजिंग क्षेत्र को देवताओं द्वारा बसाई गई पवित्र भूमि बताते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों से अपने भूमिपुत्र नेता के तौर पर पार्टी अध्यक्ष एलपी काफ्ले

का समर्थन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जन उन्मुक्ति का मतलब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और लैंगिक उत्पीड़न से छुटकारा के साथ-साथ लोगों को भय, आतंक, हत्या और बुराई से मुक्त करते हुए न्याय सुनिश्चित करना है। लेकिन मौजूदा सरकार इसमें विफल रही है। उन्होंने छत्र नेता पदम गुरुंग की मौत मामले में राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उनकी गुड गवर्नेंस का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने सरकार पर पदम गुरुंग मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में पारदर्शिता एवं जवाबदेही का नितांत अभाव है तथा राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। राई के अनुसार, आज राज्य में हजारों युवक-युवतियों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने मौजूदा सरकार को तर्क विहीन एवं तरह-तरह की बातें कर, नैरेटिव चलाकर

लोगों को भ्रमित करने वाला बताते हुए कहा कि राज्य में संप्रभु लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मौजूदा एएसकेएम सरकार केवल अपने कुछ घनिष्ठ लोगों के लिए है, जनता के लिए नहीं। लोगों की बातें सुनने की बजाय यह सरकार अब मेरे पीछे पड़ी है और एक बोलेरो और 5 करोड़ इनाम देकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है। सीएपीएस नेता ने कहा कि हमने एएसकेएम या एएसडीएफ के खिलाफ सिटीजन एक्शन पार्टी सिक्किम नहीं बनाई है और यह उससे हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई हर सिक्किमवासी को सुशासन प्रदान करने के लिए है और राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों के बारे में पता चलेगा। उनके अनुसार, राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधार लाना ही हमारा संकल्प और प्रतिबद्धता है।



वहीं, कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष एलपी काफ्ले ने अपने संबोधन में राजनीतिक नहीं बल्कि गांव के एक भाई के रूप में अपने लोगों की समस्याओं को उठाया। उन्होंने सरकार पर लिम्बू-तमांग सीट आरक्षण को लेकर गंभीर और ईमानदार नहीं होने और इन समुदायों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुधार के साथ आम लोगों के मुद्दों को गंभीरता से लिया जाएगा।

पार्टी के जिला प्रचार अध्यक्ष दहाल ने बताया कि बैठक में निर्वाचन क्षेत्र के अलावा राज्य के अन्य स्थानों के लगभग 50 लोगों ने सिटीजन एक्शन पार्टी सिक्किम में शामिल हुए। इनमें से यांगथांग निवासी जिग्मी भूटिया, दरमदीन क्षेत्र के लालन सुब्बा ने भी वक्तव्य रखा। वहीं, बैठक को पार्टी जिला कार्यकारी अध्यक्ष आंगदिला भूटिया, प्रवक्ता प्रकाश पाराजुली, सुष्मिता छेत्री, विशाल चोंग ने भी संबोधित किया। उन्होंने प्रमुखता से छत्र नेता स्व. पदम गुरुंग को न्याय दिलाने की मांग करते हुए क्षेत्र की सड़क व्यवस्था, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शैक्षणिक संस्थान आदि जैसी आम समस्याओं के समाधान में मौजूदा सरकार को विफल बताया।

विष्णु कुमार खतिवड़ा ने ली मंत्री पद की शपथ



अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 04 अगस्त। रैनाक विधानसभा के विधायक विष्णु कुमार खतिवड़ा को अपनी पार्टी और सरकार के प्रति ईमानदारी का तोहफा मिला है। वह आज एएसकेएम सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। कभी पार्टी के प्रति अपनी ईमानदारी और मुझबूझ से एएसकेएम सरकार को गिरने से बचाने वाले विधायक खतिवड़ा को पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) ने तोहफा देते हुए मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने आज राजभवन के आशीर्वाद सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) और विधानसभा अध्यक्ष अरुण कुमार उप्रेती भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि 2 फरवरी 2023 को स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉ एमके शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जिस कारण स्वास्थ्य मंत्री का पद खाली था। विधायक विष्णु कुमार खतिवड़ा को आज कैबिनेट में शामिल कर लिया गया हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा।

शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री खतिवड़ा ने कहा कि कहा कि सरकार के साथ-साथ जनता की इच्छा, चार साल में रैनाक क्षेत्र में हुए विकास और पार्टी के प्रति ईमानदारी को देखते हुए उन्हें आज मंत्री पद मिला है। उन्होंने आगे कहा कि न केवल रैनाक क्षेत्र बल्कि पाकिम जिले के अंतर्गत आने वाले सभी पांच विधानसभा के लोग सरकार के इस निर्णय से खुश हैं। उन्होंने कहा, मैं इसका श्रेय मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) को देता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि एक जनप्रतिनिधि और नेता होने के बाद कभी भी जनता और अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि मंत्री खतिवड़ा एएसकेएम पार्टी के ईमानदार नेता के रूप में जाने जाते हैं। एक समय उनकी ही पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री डॉ एमके शर्मा कथित तौर पर एएसकेएम सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे, तब उन्होंने इसका भंडाफोड़ कर एएसकेएम सरकार को बचाया था। हालांकि, श्री खतिवड़ा ने इस बात से इन्कार किया कि डॉ एमके शर्मा मंत्री पद छोड़ने के कारण उन्हें आज मंत्री पद मिला है। उनके मुताबिक उन्हें मंत्री पद उनके काम, लगन और ईमानदारी की वजह से मिला है।

आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह को लेकर सीएम की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक

अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 04 अगस्त। आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह के संबंध में आज स्थानीय मिटोकगांग में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें राज्य के मुख्य सचिव वीबी पाठक, डीजीपी एके सिंह, गृह विभाग के एसीएस होम ए सुधाकर राव, शिक्षा एसीएस आर तेलंग, आरडीडी सीसीएस डी आनंदन, शहरी विकास सचिव एमटी शेरपा, अतिरिक्त पीसीसीएफ सचिव डॉ. संदीप तांबे, संस्कृति सचिव बीके लामा, आईपीआर सचिव कर्मा

डोमा युत्सो और खेल व युवा मामलों के सचिव राजू बखेत उपस्थित थे। बैठक में मेरी माटी, मेरा देश थीम के साथ केंद्र सरकार द्वारा परिकल्पित माटी महोत्सव पर प्रमुखता से विचार-विमर्श किया गया। यह मुख्य रूप से उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसके तहत अगस्त में मातृभूमि को समर्पित कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री गोले ने सभी संबंधित विभागों को कार्यक्रम की सफलता



हेतु समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले इन कार्यक्रमों में वसुधा बंधन के तहत 75 पौधों का रोपण, वीरो की वंदना और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ

राष्ट्रगान आदि शामिल होंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का समापन 19 अगस्त को पालजोर स्टेडियम में राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में के साथ होगा।

एसकेएम सरकार सिक्किमी लोगों की बुनियादी जरूरतों के प्रति गंभीर नहीं : डीबी थापा

अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 04 अगस्त। राज्य की प्रमुख विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने मौजूदा एएसकेएम सरकार पर ताजा हमला करते हुए कहा है कि एएसकेएम शासन के बाद से राज्य में गांवों की समस्याएं बढ़ी हैं, लोगों की आय कम हो गयी है और शांति श्रृंखला टूट गयी है। वहीं, सड़कों की हालत भी जर्जर है, लेकिन सरकार इन सभी पर गंभीर नहीं है। एएसडीएफ के सिक्किम बचाओ अभियान के तहत आज मानेबुंग देताम समिति में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ये बातें कहीं। एएसडीएफ के जिला प्रचार सचिव पीबी राई ने विज्ञापित बताया कि इस दौरान, एएसडीएफ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीबी थापा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि एएसकेएम सरकार सिक्किमी लोगों की बुनियादी जरूरतों और अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं है। आज लोगों के अधिकार खरीदने की कोशिश की जा रही है या उन्हें धमकाया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने लोगों से नहीं डरने की अपील करते हुए अब जनता को नई सरकार लाने में समझदारी से सोच-समझ कर निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने सिक्किम



को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 371एफ का जिक्र करते हुए कहा कि एएसकेएम सरकार इसका बचाव नहीं कर सकी है जिसके कारण राज्य में स्थिति नाजुक और गंभीर हो गई है। उन्होंने दावा किया कि एएसकेएम सरकार ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए हैं, जिसने हमारे भविष्य को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सिक्किम-दाजिलिंग एकीकरण के मुद्दे पर भी सरकार आज तक गंभीर नहीं हुई है। अपने वक्तव्य में थापा ने एएसकेएम पार्टी को आम लोगों को डरा-धमका कर नहीं, बल्कि एएसडीएफ पार्टी से बेहतर काम करके 2024 का चुनाव जीतने की चुनौती दी। उनके अनुसार, आज एएसडीएफ पार्टी एएसकेएम की

पत्थरबाजी और अराजकता का सामना करते हुए लोगों की आवाज बन रही है। ऐसे में उन्होंने सभी लोगों से सिक्किम को बचाने हेतु एकजुट होने का आह्वान किया। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष टीएन शर्मा ने वित्त अधिनियम 2023 का मुद्दा उठाते हुए एएसकेएम सरकार पर राज्यवासियों की पहचान नष्ट करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने विधानसभा में पार्टी द्वारा सिक्किमवासियों के हितों में पारित प्रस्तावों को स्पष्ट किया। वहीं, एएसडीएफ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. एडी सुब्बा ने एएसडीएफ सरकार द्वारा राज्य में लिम्बू-तमांग समुदायों को एक जनजाति की मान्यता देने की जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिंग के नेतृत्व में लिम्बू-तमांग सीट आरक्षण को

सुरक्षित करने का भी प्रयास किया गया है। पार्टी के प्रशासनिक मामलों के उपाध्यक्ष देव गुरुंग ने भी एएसडीएफ सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए दावा किया कि एएसकेएम पार्टी के पास कोई नीति और सिद्धांत नहीं है, इसलिए वह नाम बदलकर एएसडीएफ पार्टी के ही कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रचार कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैसे एएसकेएम सरकार ने सीएए, ओएनआरसी, मोटर वाहन अधिनियम जैसे केंद्रीय कानून लाकर राज्य और इसके नागरिकों का अस्तित्व खतरे में डाल दिया है। इसके अलावा, सीएलईसी अध्यक्ष अर्जुन गुरुंग ने भी कहा कि एएसडीएफ सरकार के दौरान शुरू की गई कई परियोजनाएं आज तक

नागालैंड स्टेट लॉटरीज

डियर
सरकारी लॉटरी

M.R.P. ₹ 6

1.00 PM 6.00 PM 8.00 PM

प्रथम पुरस्कार ₹ 1 करोड़

Prize Amount for Sellers : ₹ 5 Lakhs*
(on Sale of 1st Prize Ticket)

★ TDS 5% Applicable on Seller Prize Amount (Section 194G)

WATCH LIVE DRAW in YOUTUBE

₹ 5 करोड़ के हालिया विजेता

DEAR LOHRI	DEAR DIWALI KALI PUJA	DEAR DIWALI SPECIAL	DEAR DURGA PUJA	DEAR CHRISTMAS & NEW YEAR
Mr. MUKESH SHARMA Draw Date: 16.01.2023 Ticket No. 454606	Mr. SUMAN DASMAHANTA Draw Date: 25.10.2022 Ticket No. 35290	Mr. RUDRA PRATAP MAHANTY Draw Date: 22.10.2022 Ticket No. B 824824	Mr. SUDIP MAITY Draw Date: 08.10.2022 Ticket No. 44343	Mr. ATTAR SINGH Draw Date: 01.01.2022 Ticket No. 76465

ने बनाए हैं **2390 करोड़पति**

FOR TICKETS & TRADE ENQUIRIES, CALL : 86370 06281 / 82923 49392 (SIKKIM)

टिकट सभी लॉटरी काउन्टरों पर उपलब्ध हैं

क्या आप अगले करोड़पति हैं?

कालिम्पोंग के फिल्म निर्माता व गायक अनमोल गुरुंग के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 04 अगस्त। सिक्किम की फिल्म निर्माता कंपनी सुषमा प्रोडक्शंस की कर्णधार सुषमा गुरुंग ने पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग स्थित फिल्म निर्माता और गायक अनमोल गुरुंग धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्राथमिकी गत 13 जून को दर्ज करायी गई थी।

प्राथमिकी में की गई शिकायत के अनुसार, अनमोल गुरुंग ने 2019 में एक मित्र के माध्यम से गंगटोक स्थित अपने आवास पर सुषमा गुरुंग से मुलाकात कर उनके समक्ष नेपाल में एक फिल्म में निवेश करने और निर्माता के रूप में भारत में फिल्म के अधिकार सुरक्षित करने की योजना का प्रस्ताव रखा था। उसके बाद सुषमा ने अनमोल पर भरोसा करते हुए बाबरी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बाबरी नामक फिल्म में निवेश करने पर सहमति व्यक्त की थी।

सुषमा के अनुसार, उन्होंने अनमोल को 24 जनवरी, 2020 और 2 मार्च 2020 को क्रमशः 5 लाख और 50 लाख रुपए के दो चेक जारी किये थे। इसके साथ ही फिल्म

फिल्म निर्माता सुषमा गुरुंग ने दर्ज कराई प्राथमिकी

बाबरी बनाने के दौरान आरोपी ने उनके पास एक और फिल्म कबड्डी 4 का भी प्रस्ताव रखा, जिसे बांसुरी फिल्म के बैनर तले बनाया जाना था। सुषमा को भारत में फिल्म के अधिकार के साथ-साथ डिजिटल अधिकार भी खरीदने थे। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके बाद उन्होंने कई बार बैंक के माध्यम से तथा नकदी के तौर पर भी कुल मिलाकर अनमोल को फिल्म बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए दे दिए। उन्होंने आगे बताया, कबड्डी 4 को भारत में सुषमा प्रोडक्शन के बैनर तले 17 जून 2022 को रिलीज किया गया था और विभिन्न सिनेमाघरों से राजस्व वसूली का जिम्मा अनमोल पर था।

सुषमा के अनुसार, उसे अनमोल से सितंबर-नवंबर 2022 के बीच ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए 5.90 लाख रुपए, 10-11 अक्टूबर को 1-1 लाख रुपए, 28 अक्टूबर को भी बैंक ट्रांसफर के माध्यम से 50 हजार रुपए और दिसंबर 2022 में 4 लाख नकद

रुपए मिले। कुल मिलाकर अब तक भारत में कबड्डी 4 फिल्म के बेचे गए टिकटों से राजस्व संग्रह के रूप में उन्हें अनमोल से 12.40 लाख प्राप्त हुए।

सुषमा द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में आगे कहा गया है कि बार-बार पूछताछ के बावजूद अनमोल गुरुंग ने कथित तौर पर अप्रसंगिक बहाने दिए और एकत्रित राजस्व का भुगतान करने से परहेज किया। उसके बाद शिकायतकर्ता ने 10 अप्रैल 2023 को अनमोल के अलावा सिलीगुड़ी में आईनॉक्स सिटी सेंटर और सिनेमैक्स; आईनॉक्स वेगा सर्कल, सिलीगुड़ी; ड्रीम थिएटर कालिम्पोंग; दार्जिलिंग में आईनॉक्स रिंक हॉल और को पत्र भी जारी किए।

इसके बाद सुषमा ने 27 अप्रैल 2023 को एक कानूनी नोटिस जारी किया, जिसमें भुगतान विवरण और कबड्डी 4 के लिए भुगतान की मांग की गई। अनमोल ने कथित तौर पर कानूनी नोटिस को अनदेखी की और भुगतान करने में विफल रहा।



हालांकि, सिलीगुड़ी के आईनॉक्स सिटी सेंटर द्वारा कानूनी नोटिस के जवाब में कहा गया कि उन्होंने अनमोल को कबड्डी 4 के लिए 11,87,065.23 रुपये का पूरा भुगतान कर दिया था। शिकायतकर्ता को यह भी पता चला कि अनमोल की माउंटेन स्टेरीज प्राइवेट लिमिटेड ने कबड्डी 4 के वितरक के रूप में अंबुजा रियलिटी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आईनॉक्स सिटी सेंटर, सिलीगुड़ी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके लिए वह शिकायतकर्ता सुषमा गुरुंग द्वारा अधिकृत नहीं था।

आगे एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया है कि अनमोल ने भुगतान को लेकर कई अन्य थिएटरों में कबड्डी 4 की स्क्रीनिंग की थी, जिसकी जानकारी कई अनुरोधों के बावजूद अनमोल ने सुषमा के साथ साझा नहीं की थी।

इसके अलावा, यह पता चला है कि अनमोल ने फिल्म बाबरी के लिए नेपाल में सह-निर्माताओं को 25 लाख रुपये का भुगतान किया था और केवल कबड्डी 4 के लिए 1 करोड़ रुपए के स्थान पर नेपाल में सह-निर्माताओं तक 50 लाख रुपए भुगतान पहुंचा गया, जिससे सुषमा

पर क्रमशः 25 लाख और 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा।

ऐसे में आरोपों के आधार पर पुलिस द्वारा अनमोल गुरुंग पर आईपीसी की धारा 403, 406 और 420 के तहत बेईमानी, आपराधिक उल्लंघन और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, आरोपी को पिछले महीने गंगटोक की स्थानीय अदालत से इस शर्त के साथ अग्रिम जमानत मिल गई है कि जब भी पूछताछ के लिए आवश्यकता होगी, वह पुलिस जांच अधिकारी के सामने पेश होगा।

पुलिस ने श्रीनगर में तीन आतंकवादी सहयोगियों को किया गिरफ्तार

श्रीनगर, 04 अगस्त (एजेन्सी)। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को श्रीनगर के नातिपोरा इलाके में लश्कर-ए-तैयबा की शाखा, प्रतिबंधित आतंकी संगठन टीआरएफ से जुड़े तीन आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है।

पुलिस ने बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम ने हरनबल नातिपोरा में स्थापित चेकपॉइंट पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन टीआरएफ से जुड़े तीन आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आतंकी सहयोगियों की पहचान बरामूला के बुलबुल बाग निवासी इमरान अहमद नजर, श्रीनगर के कमरवाड़ी निवासी वसीम अहमद मट्टा और पजलपोरा बिजबेहरा निवासी वकील अहमद भट्ट के रूप में हुई है।

पुलिस ने कहा कि उनसे 3 हथगोले, 10 पिस्तौल राउंड, 25 एके-47 राउंड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने कहा कि वकील अहमद भट्ट पहले प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसजेके से जुड़ा एक सक्रिय आतंकवादी था और दो साल तक जेल में बंद था। वह हाल ही में केंद्रीय जेल से जमानत पर रिहा हुआ था।

शुरुआती जांच के दौरान यह सामने आया कि तीनों ने श्रीनगर शहर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए टीआरएफ के सक्रिय आतंकवादियों से विस्फोटक पदार्थ और गोला-बारूद एकत्र किया था। इनकी गिरफ्तारी से आतंकी खतरा टल गया।

मणिपुर मुद्दे पर अनुराग ठाकुर का हमला, कहा- विपक्ष भाग रहा है क्योंकि तर्क नहीं



नई दिल्ली, 04 अगस्त (एजेन्सी)। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष पर ताजा हमला बोलते हुए उस पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'मणिपुर पर चर्चा (संसद सत्र के पहले दिन) होनी चाहिए थी। लेकिन, विपक्ष इससे भाग रहा है।

'विपक्ष ने अब तक जो किया है वह केवल देश को 'गुमराह' करने के लिए किया है। विपक्षी नेताओं को देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। उन्हें अपना अहंकार छोड़कर सदन में चर्चा में भाग लेना चाहिए।' ठाकुर ने कहा कि संसद के 15 दिन बर्बाद करने के बाद

जब इनकी जगहसाई शुरू हो गई कि दिल्ली के बिल पर सब आप पर न तर्क था न कोई अपनी बात ढंग से रख पाया। अब तक जो विपक्ष ने देश को भ्रमित करने का काम किया है, देश का समय और पैसा बर्बाद करने का काम किया है। विपक्ष भाग रहा है क्योंकि तर्क नहीं है।

विपक्ष पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में बयान की मांग कर रहा है। लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रही है।

शुक्रवार सुबह आप सांसद राघव चड्ढा और राजद सांसद मनोज कुमार झा ने मणिपुर की स्थिति पर राज्यसभा में संसर्पेशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया।

दिल्ली-एनसीआर के पांच स्टेशनों का बदलेगा रंग-रूप, पीएम मोदी छह अगस्त को रखेंगे पुनर्विकास की आधारशिला

नई दिल्ली, 04 अगस्त (एजेन्सी)। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर रेलवे के दिल्ली केंद्र, सब्जी मंडी, नरेला, गाजियाबाद व पक्रीदाबाद समेत दिल्ली मंडल के 14 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छह अगस्त को पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। चयनित स्टेशनों का पूरा स्वरूप बदलेगा और यात्रियों को वैश्विक सुविधाएं मिलेंगी। यह सुविधाएं आने वाले 30 से 40 वर्षों के मुसाफिरों के दबाव को देखते हुए विकसित होंगी। इसके साथ ही स्टेशनों में स्थानीय कला व संस्कृति को दर्शाया जाएगा। दिल्ली मंडल में 33 करोड़ की लागत आने का अनुमान है।

इस योजना के तहत चुने गए स्टेशनों के भवनों की मरम्मत की जाएगी। अगर कोई बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, तो नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रवेश और निकास

दिल्ली-एनसीआर के पांच स्टेशनों से सफर करने वाले यात्रियों को लास्ट माइल की सुविधा मिलेगी। इसके लिए स्टेशनों में इंटर मॉडल इटीग्रेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। इसमें टैक्सी, ऑटो व ई-रिक्शा की अलग-अलग लेन निर्धारित की जाएंगी। ऐसे में यात्रियों को स्टेशन से निकलने व जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए ब्रिज बनाया जाएगा।

योजना के तहत दिव्यांगों को स्टेशन से प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रैंप बनाए जाएंगे। एस्कलेटर व लिफ्ट की सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा। नीचे हो गए

द्वार के भी सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। चुने गए स्टेशनों पर यात्रियों के बैठने या फिर रुकने के लिए वेंटिंग लार्ज और कैफेटेरिया भी बनाया जाएगा। शांति और अपग्रेड होंगे। स्टेशनों के बीचों-बीच 12 मीटर चौड़ी फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा। इससे यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक आसानी से पहुंच सकेंगे। रेलवे स्टेशनों को खूबसूरत बनाकर उनका कायाकल्प करने की तैयारी चल रही है।

योजना के तहत दिव्यांगों को स्टेशन से प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रैंप बनाए जाएंगे। एस्कलेटर व लिफ्ट की सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा। नीचे हो गए

प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया जाएगा। इसी तरह यात्रियों के लिए प्रतीक्षा कक्ष के साथ वाहनों की पार्किंग की सुविधा के उचित इंतजाम किए जाएंगे। सभी स्टेशन सीसीटीवी व वाईफाई सुविधा से लैस होंगे। स्टेशनों पर बेहतर लाइटिंग की जाएगी। हर किसी को स्टेशन से प्लेटफॉर्म की जानकारी आसानी से मिल सके, इसके लिए सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे।

योजना को बड़े स्वरूप में लिया गया है। यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए उत्तर रेलवे लगातार कार्य कर रहा है। योजना पूरी होने बाद यात्रियों को स्टेशन उन्नत रूप में दिखेंगे। दिल्ली मंडल में 33 करोड़ की लागत आने का अनुमान है।

राहुल गांधी के पक्ष में आया 'सुप्रीम' फैसला तो बीजेपी ने कसा तंज, कहा- इससे तो बच गए लेकिन कब तक

नई दिल्ली, 04 अगस्त (एजेन्सी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। देश की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता को दो साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी। सजा पर रोक तो लग गई है लेकिन राजनीति इस समय जोरों पर है। भाजपा ने कहा कि संसद फिलहाल कुछ हिलाई बरत सकती है लेकिन राहुल गांधी अभी भी मुश्किल में हैं क्योंकि उनके खिलाफ कई अन्य आपराधिक मानहानि के मामले लंबित हैं।

बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए, शीर्ष अदालत ने उनकी मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर 2019 मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष उनकी सदस्यता बहाल कर सकते हैं और गांधी एक सांसद के रूप में अपनी स्थिति बहाल करने की मांग कर सकते हैं।

इस बीच, भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मावली ने एक ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भले ही इससे बच गए

हों, लेकिन कब तक? आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भले ही इससे बच गए हों लेकिन कब तक? इससे पहले एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें गलत तरीके से एक टिप्पणी के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए उनकी खिचाई की थी। साथ ही ट्वीट में कहा कि इसके अलावा, राहुल गांधी के खिलाफ कई अन्य आपराधिक मानहानि के मामले भी लंबित हैं, जिनमें स्वतंत्रता सेनानी के परिवार द्वारा दायर श्रद्धेय वीर सावरकर पर कीचड़ उछालने का हाई प्रोफाइल मामला भी शामिल है।

मालवीय ने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल गांधी भी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इनमें से किसी में भी दोषी पाए जाने पर उसे फिर से अयोग्य ठहराया जा सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लालू प्रसाद, जे जयललिता जैसे दिग्गज नेताओं को दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्यता का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी यहां मुश्किल में हैं, लेकिन फिलहाल संसद कुछ हिलाई बरत सकती है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'मोदी' उपनाम टिप्पणी मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली बार मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप सबका यहां बहुत



बहुत स्वागत है। उन्होंने कहा, 'आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसो सच्चाई की जीत होती है लेकिन चाहे जो हो मेरा रास्ता साफ है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है उसे लेकर मेरे दिमाग में स्पष्टता है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो खरियार और साथ दिया उसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर्नाटक को उनके राज्य का कावेरी जल जारी करने की सलाह देने का आग्रह करने के बाद भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस और द्रमुक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये

'जोकर' अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। लेकिन चाहते हैं कि मतदाता सोचें कि वे उनका समाधान कर सकते हैं। कांग्रेस और द्रमुक दोनों सहयोगी हैं, और विपक्षी गुट इंडिया का हिस्सा हैं।

आगे कहा कि इंडिया यानी यूपीए की दो वंशवादी पार्टियाँ कांग्रेस और डीएमके, केवल इसलिए एक साथ आई हैं क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करती हैं और अपने वंशवाद की रक्षा करना चाहती हैं और अपने विवाद को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री से मदद माँगने के लिए उन्हें पत्र लिखती हैं क्योंकि वे इसे स्वयं हल नहीं कर सकते हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर्नाटक को उनके राज्य का कावेरी जल जारी करने की सलाह देने का आग्रह करने के बाद भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस और द्रमुक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये

बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने खुली अदालत में दिया इस्तीफा



नागपुर, 04 अगस्त (एजेन्सी)। एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में, बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के जज जस्टिस रोहित बी. देव ने शुक्रवार दोपहर यहां खुली अदालत में अपना इस्तीफा दे दिया। पद छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि वह 'अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकते'।

उस वक्त वो जस्टिस एम. डब्ल्यू. चंदवानी के साथ एक खंडपीठ का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने वकीलों से माफ़ी मांगी और उन्हें अपना परिवार बताया।

अदालत में मौजूद हर वकील से माफ़ी मांगते हुए जस्टिस देव ने कहा, 'मैंने आपको डांट क्यों किया था कि आप सुधर जाएं...आप लोग कड़ों मेहनत करो।

उन्होंने कहा कि उनका इरादा कभी भी किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था क्योंकि सभी उनके लिए एक परिवार की तरह थे और 'मैं अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम

नहीं कर सकता'। 14 अक्टूबर, 2022 को न्यायमूर्ति देव और न्यायमूर्ति अनिल पंसारे की खंडपीठ ने कथित माओवादी लिंक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य को आरोपमुक्त कर दिया था और उनकी तत्काल रिहाई का भी आदेश दिया था।

हालांकि, फैसले को महाराष्ट्र सरकार द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 19 अप्रैल, 2023 को शीर्ष अदालत ने फैसले को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए किसी अन्य पीठ को सौंपने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति देव का जन्म दिसंबर 1963 में हुआ था और उन्होंने जून 2017 में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले महाराष्ट्र के महाधिवक्ता और नागपुर में अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल के रूप में कार्य किया था। वह दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले थे।

असम में 4 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त, 1 गिरफ्तार

गुवाहाटी, 04 अगस्त (एजेन्सी)। असम के करीमगंज जिले में पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा चलाए गए एक संयुक्त अभियान के दौरान 4 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आईएनएस को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को कायस्थग्राम इलाके में ऑपरेशन चलाया गया। त्रिपुरा सीमा की ओर जा रहे एक वाहन को सुरक्षाकर्मियों ने रोका और गहन जांच करने पर साबुन के डिब्बों में छिपा हुआ नशीला पदार्थ पाया गया।

अधिकारी ने कहा, हमें 50 साबुन के बक्कों में छिपा हुआ 768 ग्राम नशीला पदार्थ मिला। जब्त की गई ड्रग्स की अनुमानित कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है।

वाहन चला रहे शिफर उद्दीन को नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

सुरक्षाकर्मियों के प्रयासों की सराहना करते हुए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया: करीमगंज पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से कायस्थग्राम बाजार में एक वाहन को रोका और 768 ग्राम हेरोइन वाले 50 साबुन के डिब्बे जब्त किए। साथ ही एक आरोपी को भी पकड़ लिया। बेहतरीन टीम वर्क, इसे जारी रखो।

राहुल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना के लिए प्रियंका गांधी ने दिया बुद्ध का उद्धरण

नई दिल्ली, 04 अगस्त (एजेन्सी)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने शुक्रवार को 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में अपने भाई और पार्टी नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया और गौतम बुद्ध की पंक्तियाँ उद्धृत करते हुए कहा कि तीन चीजें सूर्य, चंद्रमा और सत्य लंबे समय तक छिप नहीं सकते।

एक ट्वीट में, प्रियंका गांधी ने कहा, 'तीन चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकतीं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य' - गौतम बुद्ध। उचित आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद। सत्यमेव जयते।

उनकी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद आई, जिसके कारण उन्हें अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि ट्रायल जज द्वारा दो साल की अधिकतम सजा देने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया था।

पाटील नेता और जाने-माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील राजिंदर चौमा, हरिन रावल और वकील तरुण चौमा और प्रसन्ना वकील राहुल गांधी की ओर से पेश



हुए। गांधी को इस साल मार्च में एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था जब सूरत को एक अदालत ने उन्हें अप्रैल 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान की गई उनकी टिप्पणी 'सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे हैं' के लिए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। गांधी की टिप्पणी की व्याख्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी और ललित मोदी के बीच एक अंतर्निहित संबंध निकालने के प्रयास के रूप में की गई।

मार्च में, सूरत की सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा अपनी सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था। कांग्रेस नेता को उस नियम के तहत अयोग्य घोषित किया गया था, जो दोषी सांसदों को लोकसभा सदस्यता से रोक्ता है।

सितम्बर माह से सीएम शुरु करेंगे सार्वजनिक मिलन कार्यक्रम : खालिंग



अनुगामिनी नि.सं.

यांगगांग, 04 अगस्त । 177वें स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर आज यांगगांग हायर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस चैलेंज कप में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव जैकब खालिंग ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आयोजकों ने उनका भव्य स्वागत किया। दीप प्रज्वलित कर शुरु हुए इस कार्यक्रम में स्कूल के छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जैकब खालिंग ने आगामी 77वें स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की सफलता की कामना की।

उन्होंने यह भी बताया कि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री गोले ने सिक्किम को पूरे जोर-शोर से चल रहे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि अगस्त माह के कार्यक्रमों की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री गोले अपना सार्वजनिक मिलन कार्यक्रम जारी रखेंगे और सितंबर में मुख्यमंत्री गोले इस क्षेत्र का दौरा करेंगे।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि वार्ड पंचायत एवं कार्यकर्ता इस उद्देश्य से व्यवस्था करेंगे कि घर का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिल सके। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में तीव्र गति से किये जा रहे विकास कार्यों से यह साबित हो गया है कि मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र को प्राथमिकता

दी है।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सिक्किम विश्वविद्यालय के निर्माण तथा भाले ढूंगा की महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा हो जाने से इस क्षेत्र को काफी लाभ होगा। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की सरकार ने लोगों की मांगों पर विचार किया है और पिछली सरकार द्वारा अधर में छोड़ी गई परियोजनाओं को जारी रखा है।

यह याद करते हुए कि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री गोले के खेल मंत्री रहते आले ग्राउंड और जोरथांग खेल मैदान के प्रायोजन को तत्कालीन सरकार ने रोक दिया था, उन्होंने कहा कि इस परियोजना को रोकने से सिक्किम के युवाओं पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की सरकार ने ऐसी नकारात्मक प्रथाओं को रोक दिया और सकारात्मक राजनीति शुरू की है।

उन्होंने कहा कि यह स्थान ऐतिहासिक होने के बावजूद कुछ स्थायी लोगों ने इस स्थान को लक्षित कर दिया है और कहा कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाने के लिए 2014 में पार्टी के उम्मीदवार की बलि दे दी थी। लेकिन अब हम सब एक मंच पर एकजुट हैं। अब सभी आपसी मतभेद भुलाकर 2024 में एसकेएम के प्रत्याशी को जिताने की प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। उन्होंने 2024 के बाद इस क्षेत्र में और विकास करने की प्रतिबद्धता भी जताई।

एसएसबी फ्रंटियर मुख्यालय के महानिरीक्षक ने की राज्यपाल से मुलाकात



अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 04 अगस्त । आज राजभवन गंगटोक में सिक्किम राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से एसएसबी, फ्रंटियर मुख्यालय, सिलीगुड़ी के महानिरीक्षक, सुधीर कुमार ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सीमा सुरक्षा, वाइब्रेंट विलेज का विकास, सहयोग और अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। महानिरीक्षक, एसएसबी ने इस बात की जानकारी प्रदान की कि एसएसबी के अंतर्गत 36 सीमा

चौकियां हैं जो देश की सुरक्षा के साथ-साथ सीमावर्ती इलाकों की आबादी की जरूरतों को भी पहचान कर सहायता प्रदान करती हैं और सीमा चौकी के दायरे में गांव के साथ अटूट बंधन स्थापित किए हुए हैं।

राज्यपाल ने अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि सशस्त्र सीमा बल का समर्पण एवं जुनून देश की ताकत है। राज्यपाल ने राष्ट्र एवं राज्य के समग्र हित के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

एसकेएम सरकार सिक्किमी

पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने एसकेएम द्वारा मानेबुंग दंताम समिधि में कोई भी विकास कार्य न करने का जिक्र करते हुए 2024 में एसडीएफ पार्टी की सरकार बनाने को आवश्यक बताया। इसी प्रकार पार्टी के संगठनात्मक उपाध्यक्ष पेम्बा सलाखा ने पवन चामलिंग के नेतृत्व में शेरपा जनजाति को मिले सम्मान और न्याय के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एसडीएफ ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने शेरपा समुदाय को न्याय दिलावाया है। बैठक को एसडीएफ में शामिल हुए अवकाशप्राप्त प्रधान निदेशक डॉ डीएस केरौंगी, महिला मोर्चा उप संयोजिका और पूर्व पंचायत श्रीमती पूर्णिमा राई, गंगटोक जिलाध्यक्ष विजय प्रधान आदि ने भी संबोधित किया। आज की बैठक में स्थानीय पारंग और श्रीनागी गांवों के एसकेएम कार्यकर्ताओं ने एसडीएफ का दामन थाम लिया।

मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, 04 जुलाई (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति अनियमितता मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा, 'अंतरिम रहत और नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई 4 सितंबर को होगी।' कोर्ट ने मामले को स्थगित करते हुए आदेश दिया।

सिसोदिया की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत देने

का आग्रह किया और कहा कि यह एक 'मानवीय' और 'वास्तविक' मुद्दा है।

उन्होंने सिसोदिया को पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट का हवाला भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति अनियमितता मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

पीठ ने टिप्पणियों की, 'दूसरा पक्ष कह रहा है कि पीठ पिछले 23 साल से बीमार है। जब हम नियमित जमानत पर सुनवाई करेंगे तो हम इसे (पत्नी की चिकित्सीय स्थिति पर अंतरिम जमानत की याचिका) उठाएंगे। हम इसकी जांच करेंगे।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू को जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया।

14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक नॉटिस जारी किया था और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा दिल्ली

मणिपुर में पुलिस चौकियों से हथियार लूट की जांच शुरु

इम्फाल, 04 जुलाई (एजेन्सी)। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह ने शुक्रवार को कहा कि बिष्णुपुर जिले में दो पुलिस चौकियों से बड़ी मात्रा में हथियारों और गोला-बारूद की लूट की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है।

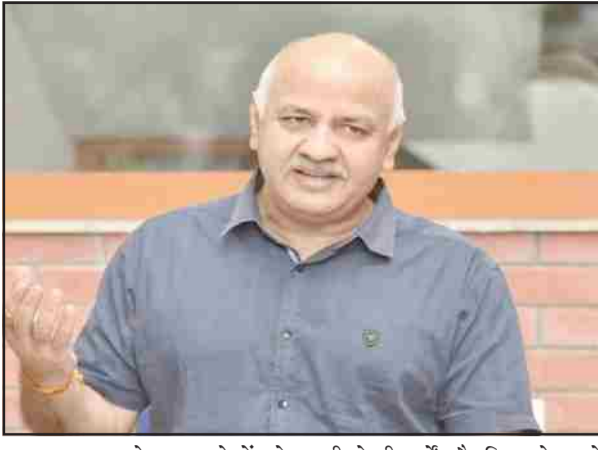
पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह ने कहा कि हथियार लूट की जांच अब पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी की निगरानी में चल रही है।

पुलिस प्रमुख ने मीडिया को बताया, 'जांच पूरी होने से पहले, हम लूटे गए हथियारों के विवरण का खुलासा करने में असमर्थ हैं।'

मणिपुर पुलिस ने गुरुवार देर रात एक बयान में कहा कि भीड़ ने बिष्णुपुर में मणिपुर सशस्त्र पुलिस की दूसरी बटालियन के कीरनफाबी पुलिस चौकी और थंगलवई पुलिस चौकियों में तोड़फोड़ की और भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद ले गए।

पुरुषों और महिलाओं की भीड़ ने उसी जिले के हिंगांग पुलिस स्टेशन और सिंगजा में पुलिस स्टेशन से हथियार और गोला-बारूद छीने का भी प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें खदेड़ दिया।

रिपोर्टों में कहा गया है कि भीड़ ने अत्याधुनिक हथियार लूट लिए, जिनमें एके और 'धातक' श्रृंखला



उच्च न्यायालय के उन आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जांच एजेंसियों से जवाब मांगा था, जिसमें उन्हें सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया।

3 जुलाई को, दिल्ली हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने मनीष सिसोदिया को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएएल) के तहत जमानत देने

की दोहरी शर्तों और ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

7 जुलाई को ईडी ने कहा कि उसने दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और कुछ अन्य आरोपी व्यक्तियों की 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

इस साल 26 फरवरी को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया और फिर ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया।

झड़पों से पहले, 30-35 कुकी-जोमी पीड़ितों का सामूहिक दफनाना, जो गुरुवार को चुरावांदपुर के तुईबुओंग में होने वाला था, मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित अत्यंष्टि स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद स्थगित कर दिया गया था।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुवार को इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) और मेइती समुदाय की एक संस्था कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रेटी (सीओसीओएमआई) को पत्र लिखकर शांति और संप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की।

ज्ञानवापी के एसआई सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

नई दिल्ली, 04 अगस्त (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस हालिया आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें एसआई को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में 'वजू खाना' को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वी. चंद्रचूड़, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एसआई) द्वारा दिए गए वचन को दर्ज किया कि वह सर्वेक्षण के दौरान स्थल पर कोई खुदाई नहीं करेगा।

शीर्ष अदालत ने आगे निर्देश दिया कि एसआई मौजूदा संरचना को कोई नुकसान पहुंचाए बिना गैर-आक्रामक पद्धति का उपयोग करके सर्वेक्षण प्रक्रिया को पूरा करेगा।

पीठ ने मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुस्सेन अहमदी के उस अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि एसआई रिपोर्टों को तब तक सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से संबंधित एक और लंबित याचिका पर फैसला नहीं हो जाता।

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किए जाने के बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटेई द्वारा वाराणसी जिला अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करने के लिए सहमत हुआ था। इससे पहले गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटेई द्वारा वाराणसी जिला अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें एसआई को सील क्षेत्र

(वजू खाना) को छोड़कर मस्जिद परिसर के बैरिकेड क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिकर दिवाकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मस्जिद समिति की उन आशंकाओं को खारिज कर दिया कि सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप संरचना को नुकसान हो सकता है। इसमें कहा गया था, 'न्याय करने के लिए सर्वेक्षण आवश्यक है। सर्वेक्षण कुछ शर्तों के साथ किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण करें, लेकिन बिना ड्रेजिंग के। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को पारित एक अंतरिम राहत में आदेश दिया था कि एसआई द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के व्यापक सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले वाराणसी कोर्ट के निर्देश को 26 जुलाई शाम 5 बजे तक लागू नहीं किया जाएगा। इसने मस्जिद समिति से वाराणसी

जिला अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा था जिला अदालत ने 21 जुलाई को एसआई को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या मस्जिद पहले से मौजूद हिन्दू मंदिर के ऊपर बनाई गई थी।

वाराणसी अदालत के आदेश में एसआई से 4 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी गई थी जब मामले की अगली सुनवाई होनी थी। हालांकि, अदालत ने उस हिस्से सर्वे से बाहर रखने का आदेश दिया, जो मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से सील कर दिया गया था। सील बंद क्षेत्र वह है जहाँ हिन्दूओं का दावा है कि एक शिवलिंग पाया गया है, जबकि मुसलमानों का दावा है कि यह एक फव्वारे का हिस्सा है।

जिला अदालत का आदेश पांच हिन्दू वादियों में से चार द्वारा दायर आवेदनों पर आया, जिन्होंने अगस्त

खड़गे ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा- पांच साल में सिर्फ 12.2 लाख नई नौकरियों का सृजन



नई दिल्ली, 04 अगस्त (एजेन्सी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में पिछले पांच साल के दौरान संगठित क्षेत्र में सिर्फ 12.2 लाख नई नौकरियों का सृजन हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों और मध्यम वर्ग के अस्तित्व के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर फेंकना जरूरी है। खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा रोजगार उपलब्ध कराने में बुरी तरह विफल रही है।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत में पिछले पांच वर्षों में संगठित क्षेत्र के केवल 12.2 लाख नई नौकरियां सृजित की गईं। इसका मतलब है कि प्रति वर्ष औसतन सिर्फ 2,44,000 नौकरियां मिलीं। खड़गे ने कहा, हम यह आंकड़े मंगलदंत नहीं बता रहे हैं। यह मोदी सरकार है जिसने यह विमर्श गढ़ा कि ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) में नियमित खाताधारकों की संख्या का मतलब उतनी नौकरियों का सृजन होता है। ईपीएफ डाटा इसकी पुष्टि

करता है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, भाजपा ने प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरियों का दावा किया था, जिसका मतलब है कि नौ वर्षों में 18 करोड़ नौकरियां पैदा की जा सकती थीं। उन्होंने दावा किया कि हमारा युवा अंधकारमय भविष्य की ओर देख रहा है।

उन्होंने कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सड़कों पर गुस्सा और हिंसा है। भाजपा रोजगार प्रदान करने में बुरी तरह विफल रही है! अकल्पनीय स्तर की बेरोजगारी, पीड़ादायक महंगाई और भाजपा द्वारा थोपी गई सुनियोजित नफरत के कारण यह विनाशकारी स्थिति पैदा हुई है।

खड़गे ने कहा, हमारे गरीबों और मध्यम वर्ग के अस्तित्व के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर करने की जरूरत है। 'ईडिया' के पास करने के लिए बहुत कुछ है। गौरिलतब है कि कांग्रेस अर्थव्यवस्था को संभालने के तरीके को लेकर सरकार पर हमला करती रही है और आरोप लगाती रही है कि वह रोजगार पैदा करने में विफल रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 04 जुलाई (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने यह देखते हुए जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया कि एक संवैधानिक पीठ पहले ही गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइलों की जांच कर चुकी है।

पीठ ने गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण से कहा, आपको इसके लिए तब दबाव डालना चाहिए था जब सुनवाई चल रही थी। भूषण ने तर्क दिया कि संविधान पीठ द्वारा मामले

की सुनवाई के दौरान गोयल की नियुक्ति जल्दबाजी में मनमाने ढंग से की गई थी।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गोयल की नियुक्ति का बचाव किया और कहा कि संविधान पीठ 'इसे रह कर सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया'।

पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और जनहित याचिका खारिज कर दी। संविधान पीठ के समक्ष भूषण ने तर्क दिया था कि गोयल, जो केंद्र सरकार के सचिव थे, ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था और उसके तुरंत बाद उन्हें चुनाव आयुक्त (ईसी) के रूप में नियुक्त किया गया था।

उन्होंने नियुक्ति के संबंध में एक आवेदन भी दायर किया था जिसमें कहा गया था कि हालांकि



संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, फिर भी सरकार ने नियुक्ति की। संविधान पीठ ने तब गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइलें मंगवाई थीं और केंद्र सरकार से यह तंत्र दिखाने को कहा था कि उन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में 'कैसे चुना गया'।

तीन सदस्यीय आयोग में एक चुनाव आयुक्त का पद सुशील चंद्रा के सीईसी पद से सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हो गया था। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनाव आयोगों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए

कॉलेजियम जैसे प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए माना था कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के एक पैनल द्वारा की जाएगी।

संविधान पीठ ने यह भी कहा था कि यह वांछनीय है कि चुनाव आयुक्त को हटाने का आधार मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह ही महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसे होनी चाहिए।

2021 में मां श्रृंगार गौरी स्थल पर निर्बाध पूजा के अधिकार की मांग करते हुए मुकुदमा दायर किया था। मस्जिद प्रबंधन समिति ने अपने जवाब में इस बात से इनकार किया कि मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाई गई थी इसने सर्वेक्षण का विरोध करते हुए कहा कि सबूत इकट्ठा करने के लिए इस तरह की कवायद का आदेश नहीं दिया जा सकता।

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दायर एक अन्य याचिका में, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने वाराणसी अदालत के समक्ष निर्देश दिया।

दायर हिन्दू उपासक के मुकदमे की स्थिरता को बरकरार रखने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस याचिका को बहाल कर दिया, जिसे 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगाने का आदेश पारित करते समय अनजाने में निपटा दिया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा भी अनजाने में हुई त्रुटि स्वीकार करने के बाद इसने लंबित अपील को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया।

NAGALAND STATE LOTTERIES	
DrawTime : 01:00 PM	
DEAR MEGHNA FRIDAY WEEKLY LOTTERY	
Draw No:18 DrawDate:04/08/23 969 F 4/-	
1st Prize Amount For Winner F 1 Crore/- + For Seller F 5 Lakhs/- 41A 72731	
2nd Prize Amount For Winner F 5000/- + For Seller F 500/-	
3rd Prize Amount For Winner F 500/- + For Seller F 500/-	
4th Prize Amount For Winner F 250/- + For Seller F 250/-	
5th Prize Amount For Winner F 125/- + For Seller F 125/-	
6th Prize Amount For Winner F 100/- + For Seller F 100/-	
7th Prize Amount For Winner F 50/- + For Seller F 50/-	
8th Prize Amount For Winner F 25/- + For Seller F 25/-	
9th Prize Amount For Winner F 10/- + For Seller F 10/-	
10th Prize Amount For Winner F 5/- + For Seller F 5/-	
11th Prize Amount For Winner F 2.5/- + For Seller F 2.5/-	
12th Prize Amount For Winner F 1.25/- + For Seller F 1.25/-	
13th Prize Amount For Winner F 0.625/- + For Seller F 0.625/-	
14th Prize Amount For Winner F 0.3125/- + For Seller F 0.3125/-	
15th Prize Amount For Winner F 0.15625/- + For Seller F 0.15625/-	
16th Prize Amount For Winner F 0.078125/- + For Seller F 0.078125/-	
17th Prize Amount For Winner F 0.0390625/- + For Seller F 0.0390625/-	
18th Prize Amount For Winner F 0.01953125/- + For Seller F 0.01953125/-	
19th Prize Amount For Winner F 0.009765625/- + For Seller F 0.009765625/-	
20th Prize Amount For Winner F 0.0048828125/- + For Seller F 0.0048828125/-	
21st Prize Amount For Winner F 0.00244140625/- + For Seller F 0.00244140625/-	
22nd Prize Amount For Winner F 0.001220703125/- + For Seller F 0.001220703125/-	
23rd Prize Amount For Winner F 0.0006103515625/- + For Seller F 0.0006103515625/-	
24th Prize Amount For Winner F 0.00030517578125/- + For Seller F 0.00030517578125/-	
25th Prize Amount For Winner F 0.000152587890625/- + For Seller F 0.000152587890625/-	
26th Prize Amount For Winner F 0.0000762939453125/- + For Seller F 0.0000762939453125/-	
27th Prize Amount For Winner F 0.00003814697265625/- + For Seller F 0.00003814697265625/-	
28th Prize Amount For Winner F 0.000019073486328125/- + For Seller F 0.000019073486328125/-	
29th Prize Amount For Winner F 0.0000095367431640625/- + For Seller F 0.0000095367431640625/-	
30th Prize Amount For Winner F 0.00000476837158203125/- + For Seller F 0.00000476837158203125/-	
31st Prize Amount For Winner F 0.000002384185791015625/- + For Seller F 0.000002384185791015625/-	
32nd Prize Amount For Winner F 0.0000011920928955078125/- + For Seller F 0.0000011920928955078125/-	
33rd Prize Amount For Winner F 0.00000059604644775390625/- + For Seller F 0.00000059604644775390625/-	
34th Prize Amount For Winner F 0.000000298023223876953125/- + For Seller F 0.000000298023223876953125/-	
35th Prize Amount For Winner F 0.0000001490116119384765625/- + For Seller F 0.0000001490116119384765625/-	
36th Prize Amount For Winner F 0.0000000745058059689378125/- + For Seller F 0.0000000745058059689378125/-	
37th Prize Amount For Winner F 0.00000003725290298449390625/- + For Seller F 0.00000003725290298449390625/-	
38th Prize Amount For Winner F 0.00000001862645149224696875/- + For Seller F 0.00000001862645149224696875/-	
39th Prize Amount For Winner F 0.000000009313227746123484375/- + For Seller F 0.000000009313227746123484375/-	
40th Prize Amount For Winner F 0.0000000046566137060617191875/- + For Seller F 0.0000000046566137060617191875/-	
41st Prize Amount For Winner F 0.000000002328306853030859375/- + For Seller F 0.000000002328306853030859375/-	
42nd Prize Amount For Winner F 0.000000001164153426515154296875/- + For Seller F 0.000000001164153426515154296875/-	
43rd Prize Amount For Winner F 0.00000000058207671325757734375/- + For Seller F 0.00000000058207671325757734375/-	
44th Prize Amount For Winner F 0.0000000002910383566286886875/- + For Seller F 0.0000000002910383566286886875/-	
45th Prize Amount For Winner F 0.00000000014551917831434444375/- + For Seller F 0.00000000014551917831434444375/-	
46th Prize Amount For Winner F 0.00000000007275958915717172221875/- + For Seller F 0.00000000007275958915717172221875/-	
47th Prize Amount For Winner F 0.0000000000363797	

खत्म हो भेदभाव

तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में स्थित मरियम्मन मंदिर में बुधवार को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच दलित परिवारों ने प्रवेश किया और पूजा अर्चना की। सौ साल से भी पुराने इस मंदिर में अब तक दलितों को प्रवेश नहीं दिया गया था। यह मामला पिछले महीने तब तूल पकड़ गया, जब उसी इलाके के एक स्कूल में पढ़ाई करके चेन्नै में काम कर रहे दो युवकों में मंदिर प्रवेश के अधिकार को लेकर सोशल मीडिया पर बहस हो गई। इनमें एक युवक दलित समुदाय का था और दूसरा वन्नियार का। सोशल मीडिया पर चली इस बहस के कारण इलाके में तनाव फैल गया और दलित एवं वन्नियार समुदाय इस सवाल पर आमने सामने हो गए। इसके बाद दलितों ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि उन्हें मंदिर में प्रवेश करने दिया जाए। जिला प्रशासन ने दलितों की ओर से घोषित की गई तारीख पर पुलिस बंदोबस्त करके यह सुनिश्चित किया कि इस दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक, किसी अन्य समुदाय ने इसके खिलाफ किसी तरह का विरोध दर्ज नहीं किया है। लेकिन गौर करने की बात है कि मंदिर में दलितों के प्रवेश को संभव बनाने के लिए इस बार भी भारी पुलिस बंदोबस्त की जरूरत पड़ी। तमिलनाडु में मंदिरों में दलितों के प्रवेश या उस पर रोक के ऐसे मामले सामने आते रहते हैं।

अप्रैल महीने में राज्य के विल्लुपुरम जिले में एक दलित के मंदिर प्रवेश पर उसकी सवर्णों द्वारा पिटाई का मामला सामने आया था। बाद में हालात बिगड़ने पर मंदिर को सील कर दिया गया। यह स्थिति तब है जब राज्य में 1947 का तमिलनाडु टेंपल एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट लागू है, जो सभी जाति और वर्ग के लोगों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश और पूजा-पाठ करने का अधिकार देता है। यही नहीं, राज्य में पेरियार के नेतृत्व में सामाजिक सुधार के तगड़े आंदोलन का इतिहास भी रहा है और इससे प्रभावित पार्टियों का यहां की राजनीति में दबदबा भी।

बहरहाल, यह स्थिति सिर्फ तमिलनाडु की नहीं, देश के तकरीबन सभी राज्यों की है। तेज विकास के कारण रहन-सहन, वेश-भूषा, काम-काज आदि के स्तरों पर आए बदलावों को देखते हुए अक्सर ऐसा लगता है कि जातिगत भेदभाव अब धुंधले पड़ रहे हैं। इसी आधार पर इसे अक्सर अतीत की बात भी कह दिया जाता है। लेकिन सचाई यही है कि आजाद देश के रूप में तीन चौथाई सदी पूरी कर लेने के बाद भी समाज के हर हिस्से में यह बात अच्छी तरह नहीं पहुंची है कि हमारा संविधान देश के हर नागरिक को समान मानते हुए उन्हें अपने धार्मिक विश्वास के मुताबिक जीवन बिताने का अधिकार देता है और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर उनमें से किसी के भी साथ भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता। जाहिर है, संविधान की इस भावना को जन-जन तक पहुंचाने के प्रयासों को पूरी शिद्दत से जारी रखना होगा।

कचरे से कंचन

राजीव आर. मिश्रा भले ही अपने उपभोक्ताओं के लिए कोयला/लिग्राइट का उत्पादन और वितरण करने का ही शासनादेश हो, फिर भी कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में कोयला और लिग्राइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) ने लीक से हटकर ओवरबर्डन से बहुत कम कीमत पर रेत का उत्पादन करने वाली एक अनोखी पहल की है। इस पहल से न केवल ओवरबर्डन के कारण रेत गाद से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद मिल रही है, बल्कि निर्माण के लिए सस्ती रेत प्राप्त करने का विकल्प भी मिल रहा है। कोयला सार्वजनिक उपक्रमों में रेत का उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है और अगले पांच वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), नैवेली लिग्राइट कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) में रेत के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए रोडमैप तैयार किया जा चुका है। कोयले का निष्कर्षण एक महत्वपूर्ण उप-उत्पाद के साथ होता है, जिसे ओवरबर्डन के नाम से जाना जाता है। कोयले के खुले खनन के दौरान, कोयले की परत के ऊपर स्थित परत को ओवरबर्डन के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में सिलिका सामग्री के साथ मिट्टी, जलोढ़ रेत और बलुआ पत्थर शामिल होते हैं। नीचे से कोयला निकालने के लिए ओवरबर्डन को हटा दिया जाता है। बाद में, कोयला निष्कर्षण पूरा होने पर, भूमि को उसका मूल आकार प्रदान करने के लिए ओवरबर्डन का उपयोग

बैकफिलिंग के लिए किया जाता है। ऊपर से ओवरबर्डन निकालते समय, मात्रा का स्बेल फैक्टर 20-25 प्रतिशत होता है। इस ओवरबर्डन को परंपरागत रूप से अपशिष्ट या बोझ माना जाता है और अक्सर इसके संभावित मूल्य को पहचाने बिना इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। हालांकि, सतत अभ्यास और संकुलर इकोनॉमी पर बढ़ते फोकस के साथ, ओवरबर्डन के लिए वैकल्पिक उपयोग की खोज करने और इसे कचरे से कंचन में बदलने की दिशा में बदलाव आया है। इस तरह के रूपांतरण की पहली व्यावसायिक पहल सीआईएल की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) ने 2016-17 के दौरान अपनी खदान में की थी। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के भानेगांव खदान में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जहां विभाग की ओर से स्थापित की गई मशीनों के जरिए रेत निकाली जाती थी। इस मशीन की क्षमता 300 घन मीटर प्रतिदिन थी। निकाली गई रेत का गहन परीक्षण किया गया और अंततः उसे नदी तल से मिलने वाली रेत से बेहतर पाया गया। इसकी कीमत लगभग 160 रुपये प्रति घन मीटर थी, जो बाजार की तत्कालीन कीमत का लगभग 10 प्रतिशत थी। यह रेत प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत कम लागत वाले घर बनाने के लिए नागपुर इम्पूवमेंट ट्रस्ट को दी गई थी। इसके अलावा दो और विभागीय पहल भी शुरू की गई। पायलट परियोजनाओं की सफलता पर, डब्ल्यूसीएल ने नागपुर के पास गोंडेगांव खदान में देश के

मंडल पार्ट-2 का सियासी रास्ता

विजय विद्रोही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 'ईडिया' और एनडीए को गेम चेंजिंग आईडिया मिल गया है। यह ओबीसी से जुड़ा हुआ है। पटना हाईकोर्ट ने ओबीसी का जातिगत सर्वे करने की मंजूरी दे दी है। उधर मोदी सरकार को रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें ओबीसी आरक्षण में कोटा की श्रेणियां करने का प्रस्ताव है। यानी मंडल पार्ट-2 का सियासी रास्ता तैयार है। 'ईडिया' तो अब तेजी से ओबीसी सर्वे की दिशा में चलेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या मोदी 'ईडिया' की रणनीति पर लंबी लकीर खींचने का जोखिम उठा पाएंगे, क्या रोहिणी आयोग की सिफारिशें लागू करने की दिशा में कोई पहल करेंगे। रोहिणी आयोग का गठन दिल्ली हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में 2017 में किया गया था। अब तक 13 बार इसके कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया है। ऐसा कहा जा रहा था कि मोदी सरकार इसे और लंबा खींचना चाहती थी, पर अचानक ही आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। आयोग का कहना है कि देश की 2,633 ओबीसी जातियों-

उपजातियों में से 983 जातियों को ओबीसी आरक्षण का शून्य लाभ मिला है, बात चाहे नौकरी की हो या पढ़ाई की। इसी तरह 994 जातियों की हिस्सेदारी नौकरी और पढ़ाई में मात्र 2.68 फीसदी की रही है। तो क्या, मोदी सरकार इन पिछड़ी 1,977 जातियों के साथ सामाजिक न्याय करने और बदले में वोट हासिल करने की चुनौती चाल चलेगी? मोदी सरकार ऐसा करती है, तो उसे पिछड़ी ओबीसी जातियों के वोट से अपने वोट बैंक का विस्तार करने में मदद मिलेगी। इस समय एनडीए के पास 25 करोड़ वोट हैं और करीब इतने ही 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से 'ईडिया' के पास हैं। अब सवाल उठता है कि इसके लिए मोदी सरकार को क्या करना होगा। बताया जाता है कि रोहिणी आयोग 2,633 ओबीसी जातियों की चार श्रेणियां बनाने के पक्ष में है। इस समय कुल आरक्षण 27 फीसदी है। इसमें से पहली श्रेणी को 10 फीसदी आरक्षण देने की बात है। दूसरी श्रेणी को नौ फीसदी, तीसरी श्रेणी को छह फीसदी और चौथी श्रेणी को दो फीसदी आरक्षण देने की बात है। सबसे नीचे की श्रेणी में सबसे पिछड़ी 1,674 जातियां रखी गई हैं, जो अब तक आरक्षण के लाभ से लगभग वंचित रही हैं। जाणकारों का कहना है कि अगर वास्तव में आयोग ने ऐसी सिफारिशें की हैं, तो मोदी सरकार ओबीसी के बड़े वर्ग को अपने साथ ले सकती है, पर यहां दो पेच हैं- एक, पिछड़ों में अगड़े-जाट और यादव नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनका कोटा 27 फीसदी की जगह 10 फीसदी ही रह जाएगा। दूसरा, महा पिछड़ी जातियों को भले ही अभी न के बराबर लाभ मिल रहा हो, पर उन्हें दो फीसदी आरक्षण देने का फैसला ज्यादा खुश करने वाला नहीं होगा। अगर इन महा पिछड़ों को मोदी समझाने में कामयाब हुए, तो खेल बदल सकते हैं। उधर 'ईडिया' को लगता है कि बिहार के ओबीसी गणना के साथ ही उनकी ओबीसी राजनीति मोदी पर भारी पड़ सकती है। मंडल आयोग ने 1911 की जनगणना के हिसाब से देश में 52 फीसदी ओबीसी होना माना था और 27 फीसदी आरक्षण दिया गया था। देश में कितने ओबीसी हैं, यह संख्या किसी को पता नहीं है। एक अध्ययन के अनुसार, देश में ओबीसी

जनजातीय इलाकों में जमा है गुस्सा

मधुरेंद्र सिन्हा भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर पिछले कुछ महीनों से बड़े पैमाने पर हिंसा के कारण सुखियों में है। वहां अब तक लगभग डेढ़ सौ जानें गईं और सैकड़ों मकान फूट डाले गए। लाखों लोगों ने जान बचाकर राहत शिविरों में शरण ली या दूसरे राज्यों में पलायन कर गए। वहां रहने वाले मैतेई और कुकी जनजाति के बीच परस्पर भरोसे की दीवार ढह गई। हालांकि दोनों समुदाय पहले से ही एक-दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन इन जातीय दंगों ने उनके बीच अब बड़ी खाई खोद दी है। दोनों प्रमुख समुदायों में नफरत की भावना इस कदर घर कर गई है कि दोनों एक-दूसरे को

देखना भी नहीं चाहते। विभिन्न टि्वरपणीकार इस भयावह हिंसा और मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं के कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन राज्य प्रशासन अब तक इस हिंसा पर काबू पाने के लिए कुछ ठोस नहीं कर पाई है। नतीजतन सर्वोच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है और उसने वहां के पुलिस महानिदेशक को तलब किया है। मणिपुर की इस अभूतपूर्व हिंसा का एक कारण है अफीम की अवैध खेती और ड्रग्स तस्करी, जिसमें न केवल कुकी जनजाति के लोग, बल्कि सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों के रिश्तेदार भी शामिल हैं। मणिपुर अफीम तस्करी के लिए आजादी के

बाघ संरक्षण में बड़ी उपलब्धि

हरेंद्र सिंह बरगली बाघों की 2022 आबादी आकलन रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड 560 बाघों के साथ भारत में तीसरा सबसे अधिक बाघों वाला प्रदेश है, जो तुलनात्मक रूप से प्रदेश के छोटे भौगोलिक क्षेत्रफल को देखते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्ष 2018 की गणना में प्रदेश में बाघों की संख्या 442 थी। उत्तराखंड में बाघों के संरक्षण के लिए दो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र, कॉर्बेट बाघ अभयारण्य और राजाजी बाघ अभयारण्य तराई आर्क भूभाग के पश्चिमी हिस्से में स्थित हैं। उत्तराखंड में स्थित तराई आर्क भूभाग बाघ संरक्षण में सफल रहा है, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के कारण इस भूभाग में विगत वर्षों में हुए कई बदलावों के चलते महत्वपूर्ण बाघ आवासों के बीच जंगली जानवरों का परस्पर आवागमन खतरे में है। पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण जंगलों को मानवजनित दबाव का सामना करना पड़ा है। कृषि क्षेत्रों का विस्तार, बढ़ती आबादी, शहरीकरण, उपजाऊ खेतों का मानव बस्तियों में बदलना, रेत खनन और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं इस भूभाग के भीतर वन्यजीवों के निवास स्थान के नुकसान का कारण बनी हैं। कॉर्बेट बाघ अभयारण्य बाघों की महत्वपूर्ण आबादी (2022 के आकलन में 260 बाघ) के लिए जाना जाता है, जहां बाघों का आबादी-घनत्व उच्चतम है। जैव-विविधता से भरपूर कॉर्बेट में बाघों के अलावा 1,200 से अधिक हाथियों, चार प्रकार की हिरण प्रजातियों, भालू की दो प्रजातियों, अन्य वन्य जीव प्रजातियों सहित सैकड़ों पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। बाघों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए कॉर्बेट और अन्य वन प्रभागों के बीच जानवरों के आवागमन हेतु जंगलों का आपस में जुड़ा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कॉर्बेट बाघों को पड़ोसी वन प्रभागों में फैलाने के लिए एक स्रोत के रूप में कार्य करता है। उत्तराखंड में पश्चिमी तराई आर्क भूभाग के भीतर स्थित लगभग 1,150 वर्ग किलोमीटर में फैला राजाजी बाघ अभयारण्य दूसरा महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। क्षमता के विपरीत यह अभयारण्य अभी तक विभिन्न कारणों से बाघ संरक्षण में उतना प्रभावी योगदान नहीं दे पाया है, क्योंकि महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे अत्यधिक दबाव में आ गए हैं और मानवीय गतिविधियों, बुनियादी ढांचे के विकास और आसपास के परिदृश्य में तेजी से बदलाव के कारण जंगलों की निरंतरता में और अधिक खिंचडन का खतरा है। वर्ष 2022 में आयोजित बाघ गणना में राजाजी में 54 बाघों का अनुमान लगाया गया है। यह संरक्षण की तत्काल पहल की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। कॉर्बेट से पश्चिमी राजाजी टीआर में बाघों को स्थानांतरित करने का सरकार का निर्णय वास्तव में बाघ संरक्षण प्रयासों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में केवल दो छोटे और खंडित गलियारे हैं, जो राजाजी और कॉर्बेट को जोड़ते हैं। एक गलियारा लैंसडाउन वन प्रभाग में शिवालिक पहाड़ियों से होकर गुजरता है, जबकि दूसरा हरिद्वार और बिजनौर वन प्रभाग के शिवालिक तलहटी के जंगलों से होकर गुजरता है। दुर्भाग्य से, बाद वाला गलियारा गंभीर दबाव में है, क्योंकि यह कृषि और मानव बस्तियों वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इसके अलावा, शहरीकरण और सड़क निर्माण वन्यजीवों की आवाजाही के लिए चुनौतियां खड़ी करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर यातायात की अनियमित गति तथा स्पीड ब्रेकरों को हटाने के कारण वन्यजीवों को कोसी नदी में पीने के पानी तक पहुंचने और रामनगर वन प्रभाग में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न होती है। कॉर्बेट के पास के गांव पर्यटन केंद्रों में परिवर्तित हो रहे हैं और वहां कई रिसॉर्ट और होटल बनाए जा रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण बाघ आवास भी खिंचडन और गलियारों के नुकसान के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बाघ संरक्षण प्रयासों के अगले चरण में वन्यजीवों के आवासों की कनेक्टिविटी को संरक्षित और बहाल करना प्राथमिकता में होना चाहिए। पश्चिमी तराई आर्क भूभाग के भीतर बाघ, हाथी तथा अन्य प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए भूभाग-स्तरीय संरक्षण नीति को अपनाना और संरक्षण उपायों को, जो वन्यजीवों के आवास स्थानों के बीच कनेक्टिविटी, मानव-वन्यजीव संघर्ष के उचित प्रबंध और अवैध शिकार से इन क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करते हों, लागू करना अत्यंत आवश्यक है।

वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई के दौर में आरक्षण का मुद्दा बेहद संवेदनशील है, जो बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। ऐसे में आरक्षण के कोटे में जरा-सा भी फेरबदल कुछ के लिए खुशी लाएगा और कुछ के लिए संकट। बीच का रास्ता कोई है नहीं। इसलिए केंद्र सरकार जातीय जनगणना करवाना नहीं चाहती। इस हिसाब से रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट फिलहाल ठंडे बस्ते में डाली जा सकती है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी को लगा कि 2024 का आम चुनाव जीतना मुश्किल होगा, तो जनवरी में कमंडल यानी राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही मंडल-2 (वर्गीकरण) को लागू करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

भी इसके पड़ोसी देश हैं। ये उस कुख्यात ड्रग तस्करी क्षेत्र का हिस्सा हैं, जिसे स्वर्ण त्रिभुज कहते हैं और इसमें तीनों देश-लाओस, थाईलैंड और म्यांमार शामिल हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है। यहां से तस्करी के जरिये अफीम पहले चीन में भी पहुंचाई जाती थी, लेकिन कम्युनिस्ट शासन में वहां उसकी तस्करी कम हो गई। लेकिन भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड में बाकायदा इसकी आपूर्ति होती रही। साठ के दशक में तो वियतनाम युद्ध के दौरान वहां की अफीम अमेरिकी सैनिकों में बेहद लोकप्रिय हो गई थी। लेकिन वियतनाम युद्ध खत्म होते ही यह धंधा चोपट हो गया। उसके बाद से तस्करोर ने बड़े पैमाने पर अफीम भारत भेजना शुरू किया। फिर मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में अफीम की खेती होने लगी।

पहले की सरकारों इसे अनदेखा करती रहीं, लेकिन बीरेन सिंह की भाजपा सरकार ने इस पर निशाना साधा। सरकारी एजेंसियों ने हजारों एकड़ में लगी अफीम की फसल जलानी शुरू की, जिससे स्थानीय लोगों में सरकार के खिलाफ काफी रोष पैदा हो गया। माना जाता है कि जातीय हिंसा का एक कारण यह भी बना और मैतेई तथा कुकी समुदायों के बीच दंगों की एक बड़ी वजह यही है।

मणिपुर की ड्रग समस्या जटिल है और जनजातीय इलाकों में रहने वाले बहुत से लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि इसमें मोटा पैसा आसानी से मिल जाता है। इसने कुकी जनजाति के एक बड़े वर्ग को प्रभावित किया है, जिसका गुस्सा मणिपुर की हिंसा में साफ दिखाई दे रहा है।

आलिया भट्ट ने दीपिका पादुकोण के लुक को किया कॉपी

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया है। इस दौरान वो ओवरसाइज्ड ड्रेस में नजर आईं। लेकिन एक्ट्रेस का ये लुक लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया। लेटेस्ट फोटोज को देखने के बाद लोगों ने यह कहा है कि आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण का लुक कॉपी किया है। ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा अभिनीत 'कोई मिल गया' जल्द ही अपनी 20वीं सालगिरह मनाएगी। यह फिल्म अपने प्रशंसकों के दिलों में एक खास जगह रखती है। इस विशेष अवसर का जश्न मनाने के लिए, फिल्म निर्माताओं ने 4 अगस्त को 30 शहरों में फिल्म को फिर से रिलीज करने का फैसला किया है। साईस-फिक्शन ड्रामा को युवा और बुजुर्ग दोनों दर्शकों ने खूब सराहा। बॉलीवुड स्टार रानी मुखर्जी मेलबर्न आईएफएफएम के आगामी भारतीय फिल्म महोत्सव में एक अभिनेता के रूप में अपने करियर और जीवन के बारे में विस्तार से बताते हुए एक मास्टरक्लास देंगी। यह विशेष कार्यक्रम फिल्म महोत्सव के 14वें संस्करण से एक दिन पहले 10 अगस्त को होगा। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुखर्जी अपनी कुछ प्रतिष्ठित भूमिकाओं और फिल्मों के बारे में बात करेंगी और एक अभिनेता के रूप में अपनी कला और अनुभवों के बारे में जानकारी साझा करेंगी।

एक्ट्रेस अदा शर्मा हुई बीमार

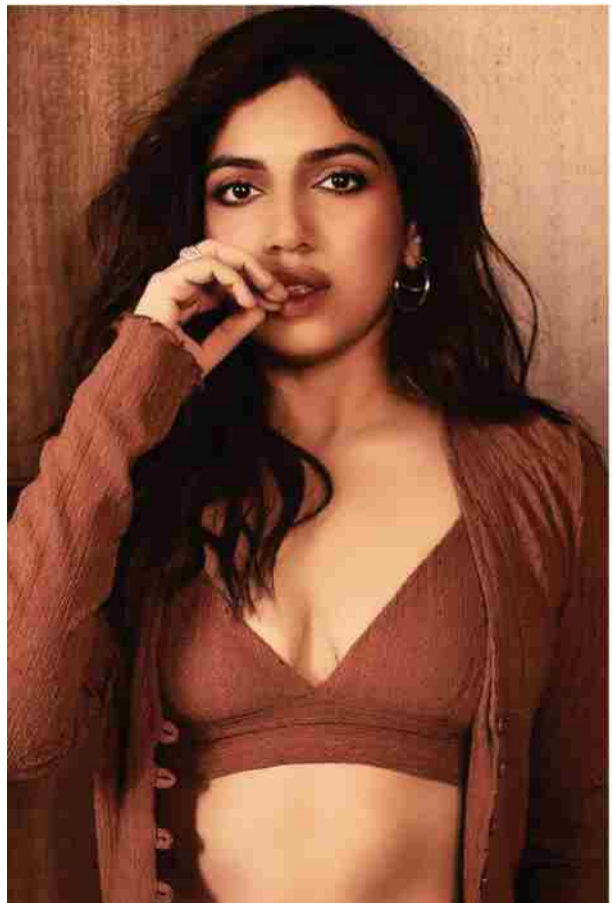


द केरल स्टोरी फेम एक्ट्रेस अदा शर्मा को फूड एलर्जी और डायरिया के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया है। वह फिलहाल चिकित्सकों की निगरानी में है। एक्ट्रेस को अपकमिंग शो कमांडो के प्रमोशन से ठीक पहले मंगलवार को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया गया। उन्हें डायरिया और फूड एलर्जी का पता चला। सूत्र के मुताबिक वह स्ट्रेस हील्स और डायरिया से पीड़ित हो गईं। फिलहाल, वह निगरानी में हैं। हालांकि अदा को कमांडो का प्रचार करते देखा गया है जहां वह भावना रेड्डी की भूमिका निभा रही हैं। बता दें कि कमांडो नई एक्शन-थ्रिलर सीरीज जल्द ही आने वाली है, और इसमें एक्ट्रेस अदा के साथ मुख्य भूमिका में एक्टर प्रेम हैं। सीरीज द केरल स्टोरी की सफलता के बाद अदा और विपुल अमृतलाल शाह फिर साथ आए हैं। विपुल ने इस सीरीज का निर्देशन किया है। इसमें वैभव तत्ववादी, श्रेया सिंह चौधरी, अमित सियाल, तिगांशु धूलिया, मुकेश छाबड़ा और इशतयाक खान भी हैं।

भूमि पेडनेकर बोलीं- हर फिल्म में देती हूं अपना 200 प्रतिशत

बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने अपनी जबरदस्त अदाकारी से इंडस्ट्री में एक अलग जगह बनाई है। भूमि ने हमेशा अपने अभिनय और अपने द्वारा निभाए गए हर किरदार में प्रमाणिकता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। भूमि पेडनेकर इंडस्ट्री में सबसे अधिक डिमांड वाली एक्ट्रेसों में से एक हैं। वहीं भूमि पेडनेकर का कहना है वह अपनी हर फिल्म में अपना 200 प्रतिशत देती हैं। उन्होंने कहा, मैं काम करने की शौकीन हूँ। इसलिए, मैं जो भी फिल्म करती हूँ, उसमें अपना 200 प्रतिशत देती हूँ। अभिनय एक खास पेशा है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक्ट्रेस ने कहा, जब भी मैं किसी फिल्म के सेट पर कदम रखती हूँ, मैं कृतज्ञता से भर जाती हूँ कि मेरा काम मुझे किसी तरीके से अविस्मरणीय बना देगा। मुझे इस तथ्य से प्यार है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ, जो अपने जीवन का हर पल कुछ ऐसा कुछ बनाने की कोशिश में बिताती हूँ जो हमेशा रहे। भूमि पेडनेकर ने कहा, मुझे लगता है कि मैं अपनी फिल्मों के जरिए महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हूँ, क्योंकि फिल्में हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। मैं हमेशा से एक ऐसी अभिनेत्री बनना चाहती थी, जिसका मेरी फिल्मों और मेरे द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के जरिए सांस्कृतिक प्रभाव पड़े।

भूमि ने कहा, मेरे पास हमेशा ऐसी ही परियोजनाएं होती हैं और मैं ऐसी ही परियोजनाएं चुनूंगी जो मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं अपने काम के जरिए अपने लिए एक विरासत बना रही हूँ और मैं स्क्रीन पर जो काम करती हूँ उस पर गर्व करना चाहती हूँ।



'लाइफ लॉजिक नहीं मैजिक का खेल है', अभिषेक बच्चन की 'घूमर' का दमदार ट्रेलर रिलीज

बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन और सैयामी खेर की अपकमिंग फिल्म 'घूमर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो दर्शकों को भावनाओं, प्रेरणा और परिवर्तनकारी कहानी कहने की दुनिया की एक झलक पेश करता है। फिल्म का ट्रेलर पहले 3 अगस्त को रिलीज होने वाला था, लेकिन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के निधन के बाद इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। अभिषेक बच्चन, सैयामी खेर और निर्देशक आर बाल्की की असाधारण प्रतिभाओं से सजी 'घूमर' भारत में स्पॉट्स फिल्मस के परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने का वादा करती है। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन एक कोच का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं, जिसके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जब वह एक लकवाग्रस्त खिलाड़ी से मिलते हैं, जिसका किरदार प्रतिभाशाली सैयामी खेर ने निभाया है। फिल्म में दोनों को सामाजिक चुनौतियों और व्यक्तिगत संघर्षों के खिलाफ सामना करना पड़ता है। जबकि इसका श्रेय निर्देशक आर. बाल्की को जाता है, जो विशिष्ट कहानी कहने की क्षमता प्रदर्शित करने वाले अद्भुत डायरेक्टर हैं। अभिषेक और सैयामी का शक्तिशाली प्रदर्शन दर्द, दृढ़ संकल्प और आशा के क्षण प्रदान करता है। निर्देशक आर बाल्की की विशिष्ट शैली उनकी कहानियों को सहजता से बुनती है। साथ ही यह फिल्म दर्शकों को एक परिवर्तनकारी यात्रा पर जाने के लिए

दुलकर सलमान को है पंजाबी संगीत से बेहद प्यार

गायक दुलकर सलमान को पंजाबी संगीत से बेहद प्यार है। गन्स एंड गुलाल्स में अपने काम से एक बार फिर दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार स्टार दुलकर सलमान का कहना है कि उन्हें पंजाबी संगीत बहुत पसंद है और वह वर्तमान में रैपर एपी दिल्ली के ट्रैक पर थिरक रहे हैं। दुलकर ने कहा, मैं सभी प्रकार के फेज से गुजरता हूँ। अभी मैं दिल्ली में हूँ। मैं वास्तव में एपी दिल्ली से प्यार करता हूँ। मुझे अपने कॉलेज के दिनों से ही पंजाबी संगीत से बहुत प्यार है, जब मैंने पहली बार इसे सुना था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यूरो पंजाबी, पंजाबी पॉप उस समय का है जब मैं 2000 के दशक की शुरुआत में कॉलेज में था, मुझे लगता था कि शायद पिछले जीवन में मैं पंजाबी था। लेकिन इसे सुनना हमेशा अच्छा लगता है। अभिनेता ने आगे कहा कि मैं इससे बहुत आसानी से जुड़ जाता हूँ। गौरतलब है कि गन्स एंड गुलाल, राज एंड डीके द्वारा बनाई गई एक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर थ्रुखला है। यह 18 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। सीरीज में राजकुमार राव, आदर्श गौरव और गुलशन देवैया भी हैं। दुलकर सुपरस्टार ममूटी के बेटे हैं।



आमंत्रित करती है, जो पूर्वकल्पित धारणाओं को चुनौती देती है। 'घूमर' में अभिषेक बच्चन और सैयामी खेर मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसके अलावा शबाना आजमी और अंगद बेदी भी फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं। यह अमिताभ बच्चन की एक कमेटेटर के रूप में पहली फिल्म है। यह फिल्म शिवेंद्र सिंह और इवाका दास की भी पहली फिल्म है। फिल्म को आर. बाल्की ने डायरेक्ट किया है। वहीं होप प्रोडक्शंस और सरस्वती एंटरटेनमेंट द्वारा इसका निर्माण हुआ है। घूमर 18 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ब्लैक बिकिनी में नजर आई किम कार्दशियन

हॉलीवुड स्टार किम कार्दशियन हमेशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैस के साथ अपनी बॉल्ड फोटोज शेयर करती रहती हैं और इनकी तस्वीरें इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल होती हैं। इसी बीच किम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से बाथ लेते हुए की कुछ फोटोज शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब कहर बरपा रही हैं। किम की इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किम कार्दशियन ब्लैक बिकिनी पहने स्विमिंग करती नजर आ रही हैं। एक अन्य फोटो में बिकिनी पहन वह पानी में खूब गोते लगा रही हैं। नहाने के बाद पूल से बाहर निकल वह अपना कर्वी फिगर पलॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं। अभिनेत्री का ये लुक देख उनके फैस के होश उड़ गए हैं। एक्ट्रेस की ये फोटोज इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं।

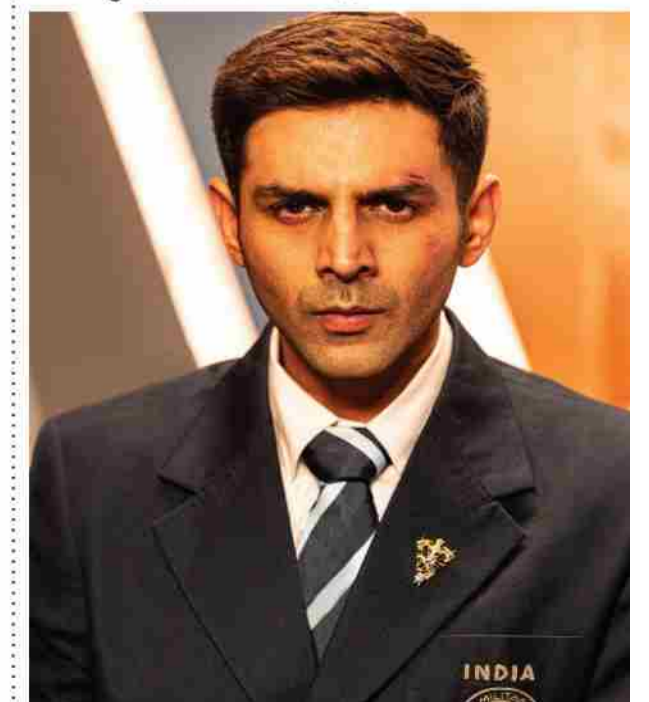


फरदीन और नताशा होंगे अलग-अलग

बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान और उनकी पत्नी नताशा माधवानी में तलाक होने वाला है। फरदीन और नताशा एक साल से ज्यादा समय से अलग रह रहे हैं। एक इंटरव्यू में फरदीन ने कहा था, हम एक परिवार बनाने के लिए बहुत उत्सुक थे, नताशा और मैं, हमारे सामने बच्चे पैदा करने की चुनौतियाँ थीं इसलिए हमें आईवीएफ मार्ग अपनाना पड़ा। यहाँ मुंबई में डॉक्टरों के साथ हमारा अनुभव बुरा था और नताशा को वास्तव में कष्ट सहना पड़ा, यह शरीर और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत कठिन है। उन्होंने यह भी कहा था, 2011 में, हम लंदन चले गए, हमें वहाँ एक बहुत अच्छा डॉक्टर मिला। उनकी शुरुआती गर्भावस्था में से एक में, हमारे जुड़वाँ बच्चे थे, और उन्होंने छह महीने में उन्हें खो दिया। तो यह बहुत कठिन था हमारे लिए, यह एक कठिन समय था। उसने एक जीवित बच्चे को जन्म दिया, और हमने बच्चों को खो दिया। अंततः हमारी बेटी हुई, उसने हमें बहुत खुशी दी। इसलिए जब आप कुछ इस तरह से गुजरते हैं, तो आप जीवन को और अधिक संजोते हैं गहराई से, इसलिए जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो उसने मुझे खुशी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरदीन हॉरर ड्रामा विस्फोट से फिल्मों में वापसी करने के लिए तैयार हैं। फिल्म में रितेश देशमुख, प्रिया बापट और क्रिस्टल डिसूजा भी होंगे। उनके 2005 की हिट फिल्म नो एंटी के सीकल में भी अभिनय करने की खबर है। उन्हें आखिरी बार बड़े पर्दे पर 2010 में दूल्हा मिल गया में देखा गया था। बता दें कि जहाँ फरदीन अपनी मां के साथ मुंबई में रहते हैं, वहीं नताशा लंदन में हैं। वह दिग्गज अभिनेता मुमताज की बेटी हैं। फरदीन और नताशा दिसंबर 2005 में शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों एक बेटी जयानी इसाबेला खान और एक बेटे, अजरियस फरदीन खान के माता-पिता हैं।

कार्तिक आर्यन बनें चंदू चैंपियन

कार्तिक आर्यन स्टार कबीर खान के निर्देशन में बन रही अपकमिंग स्पॉट्स ड्रामा चंदू चैंपियन ने अपनी घोषणा के बाद से ही लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। ऐसे में जबकि हार न मानने वाली इस असाधारण रियल लाइफ स्टोरी को देखने का उत्साह तेज है, निर्माता ने फिल्म से चंदू बनें कार्तिक आर्यन का पहला लुक रिलीज कर दिया है, जिसे देख वास्तव में लोगों को गर्व महसूस होगा। चंदू के रूप में कार्तिक आर्यन का फर्स्ट लुक आखिरकार सामने आ गया है, जिसमें सुपरस्टार को पूरी तरह से किरदार में डूबा हुआ दिखाया गया है। छोटे बाल और भारत का ब्लेजर पहने कार्तिक ने फिल्म के लिए पहले कभी न देखा गया लुक अपनाया है। इसने वास्तव में फिल्म की रिलीज के लिए उत्साह को एक पायदान ऊपर बढ़ा दिया है। इस फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों पहले लंदन में साजिद और वर्धा नाडियाडवाला की मौजूदगी में शुरू हुई है। फिल्म के मुहूर्त शॉट के दौरान कबीर खान और कार्तिक आर्यन के साथ स्पेशल गेस्ट मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मीडिया एंड स्पॉट्स आरटी माननीय स्टुअर्ट एंड्रयू भी सेट पर मौजूद थे। बता दें, यह कार्तिक और कबीर की पहली और नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के साथ दूसरी साझेदारी होगी। यह वास्तव में एक बड़ी घोषणा है क्योंकि इंडस्ट्री के तीन दिग्गज एक खिलाड़ी की असल जिंदगी की दिलचस्प कहानी लाने के लिए एक साथ आए हैं। साजिद नाडियाडवाला और कबीर खान द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित, चंदू चैंपियन का निर्देशन कबीर खान द्वारा किया जा रहा है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 14 जुलाई 2024 को रिलीज होगी।



ऑस्ट्रेलियाई ओपन में हारी हारी सिंधु सिडनी ।

भारत की महिला बैडमिंटन स्टार पी वी सिंधु अमेरिकी ओपन में हार के साथ ही बाहर हो गयी हैं। सिंधु को महिला एकल क्वार्टर फाइनल में चीनी मूल की अमेरिकी खिलाड़ी बेवेन झांग ने सीधे गेम में 21-12, 21-17 से हराया। ये मुकाबला अधिक घंटे से कुछ अधिक समय चला। सिंधु अब विश्व रैंकिंग में 17वें स्थान पर खिसक गयी हैं। सिंधु ने यहां अपने ही देश की अम्पिता चालिहा और आकार्षि कश्यप को पहले दो दौर में हराया था पर झांग के खिलाफ वह हारवी नहीं हो पायीं। अब वह 21 से 27 अगस्त तक डेनमार्क के कोपेनहेगन में विश्व चैम्पियनशिप खेलेंगी। विश्व चैम्पियनशिप 2019 विजेता सिंधु चोट से उबरने के बाद से ही लय में नहीं हैं। वह इस साल 12 बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर टूर्नामेंटों में से सात में शुरूआत में ही बाहर हो गईं। साल की शुरूआत में उन्होंने अपना कोच भी बदला था पर उससे भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा।



भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पहले मैच में चीन को 7-2 से हराया

चेन्नई ।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में चीन को 7-2 से हरा दिया। इस मैच में भारतीय टीम ने एक मैदान गोल किया जबकि छह गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए हुए। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम बेहतर गोल अंतर के आधार पर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गयी है। भारतीय टीम की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह और वरुण कुमार ने दो-दो गोल दागे। करमनप्रीत ने पांचवें और आठवें जबकि सुखजीत सिंह ने 15 वें मिनट में एक गोल किया। आकाशदीप सिंह ने 16 मिनट में

एक और गोल कर भारतीय टीम की बढ़त को बढ़ा दिया। वरुण कुमार ने 19 वें और 30 वें जबकि मनदीप सिंह ने 40 मिनट में एक गोल दागकर भारतीय टीम को अपराजेय बढ़त दिलायी। वहीं चीन की ओर से वहीवेनहुई ने 18 वें और जिंशेंग गाओ ने 25 वें मिनट में एक-एक गोल किया। भारतीय टीम के उपकप्तान हार्दिक ने मैच के बाद कहा, 'पेनल्टी कॉर्नर हमारी ताकत है और हम इस



विकल्प का पूरा इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि पेनल्टी पर गोल हो रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। उन्होंने कहा, 'हमारा लक्ष्य पेनल्टी कॉर्नर की दर अच्छी बनाये रखना और कम से कम दो या

तीन गोल उसके जरिए करना है। इसके अलावा हमें हर क्वार्टर में अवसर बनाने हैं। भारत को अब शुरूआत को जापान से खेलना है। उसमें भी टीम जीत के इरादे से उतरेगी।

इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास



लंदन ।

इंग्लैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने शुरुआत को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास की घोषणा की।

हेल्स ने अगस्त 2011 में मैग्नेटोर में टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने 11 टेस्ट, 70 एक दिवसीय और 75 टी20 में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। अंतरराष्ट्रीय मंच पर हेल्स की आखिरी प्रभावशाली पारी भी भारत के खिलाफ थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में 47

गेंदों में 86 रन (चार चौके और सात छके) की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। हेल्स और जोस बटलर (नाबाद 80) ने एशियाई में 169 रनों का पीछा करते हुए इंग्लैंड को 10 विकेट से जीत दिलाई थी। हेल्स ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। तीनों प्रारूपों में 156 मैचों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने जीवन भर के लिए कुछ यादें और कुछ दोस्त बनाये हैं। मुझे लगता है कि

अब आगे बढ़ने का सही समय है। हेल्स ने इंग्लैंड के लिए अपना आखिरी मैच 2022 के टी20 विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में खेला था। उन्होंने कहा, 'इंग्लैंड की जर्सी में कुछ ऊंचाइयों के साथ नाकामियों को भी अनुभव किया है। इस एक अविश्वसनीय यात्रा के दौरान मुझे बहुत संतुष्टि महसूस हो रही है कि इंग्लैंड के लिए मेरा आखिरी मैच विश्व कप फाइनल जीतना था। हेल्स 2019 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड की टीम का हिस्सा

नहीं थे। इंग्लैंड से जुड़े मामलों में उन्हें 21 दिन के लिए प्रतिबंधित किया गया था और तत्कालीन कप्तान इयोन मोर्गन ने इसे 'पूरी तरह से भरोसा तोड़ने वाला करार दिया था। हेल्स ने हालांकि सफेद गेंद (सीमित ओवरों की क्रिकेट) में इंग्लैंड की टीम को फिर से शीर्ष पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी 92 गेंद की 147 रन की पारी के दम टीम ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छह विकेट पर 481 रन बनाये थे। वह एकदिवसीय क्रिकेट का दूसरा

सर्वोच्च स्कोर है। उन्होंने 70 एकदिवसीय में छह शतक और 14 अर्धशतकों की मदद से 37.79 की औसत के साथ 2419 रन बनाये हैं। इस आक्रमक बल्लेबाज से 75 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 30.95 का औसत से 2074 रन बनाये। इस प्रारूप में उन्होंने एक शतक और 12 अर्धशतक लगाया। वह 11 टेस्ट में पांच अर्धशतक की मदद से महज 573 (27.28 की औसत के साथ) रन ही बना सके।

देश भर में खोलेंगे 1,000 खेलो इंडिया केंद्र : ठाकुर 227 केन्द्र पूर्वोत्तर राज्यों में होंगे



नई दिल्ली ।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि देश भर में इस साल एक हजार खेलो इंडिया केंद्र खोल जाएंगे। साथ ही कहा कि इसमें से 227 केंद्र पूर्वोत्तर राज्यों में खोले जाएंगे। ठाकुर ने कहा कि सरकार का प्रयास देश के हर जिले में एक खेलो

इंडिया केंद्र खोलने का है पर पूर्वोत्तर राज्यों में हर जिले में दो केंद्र खोलने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को कई सफलताएं दिलाई हैं। इसलिए सरकार उस क्षेत्र में खेल संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए करीब 75 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गयी है जिनमें करीब 520.60 करोड़ रुपये का खर्च आया। ठाकुर ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य देश में खेल महाशाक्ति केंद्र हैं और इन्होंने देश को कई अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त खिलाड़ी दिए हैं। उन्होंने कहा कि खेल के राज्य का विषय होने के कारण खेल अवसरचना के विकास सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की ही है और केंद्र का काम इसमें उनकी सहायता करना है।

बीसीसीआई ने मीडिया अधिकारों को लेकर जारी की निविदाएं , डिजिटल अधिकारों का बेस प्राइज टीवी रखा

मुंबई ।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने आने वाले टूर्नामेंटों के लिए मीडिया अधिकारों को लेकर निविदाएं जारी कर दी गयी हैं। इसमें टीवी से अधिक बेस प्राइज (आधार मूल्य) डिजिटल अधिकारों के लिए रखा है। यह पहली बार हुआ है जब डिजिटल अधिकारों के लिए आधार मूल्य ज्यादा है। बीसीसीआई ने मीडिया अधिकार चक्र के लिए कुल आधार मूल्य को घटाकर 45 करोड़ रुपये प्रति मैच कर दिया है। यह पहली बार हुआ है जब डिजिटल अधिकारों के लिए आधार मूल्य ज्यादा है। बीसीसीआई ने मीडिया अधिकार चक्र के लिए कुल आधार मूल्य को घटाकर 45 करोड़ रुपये प्रति मैच कर दिया है। यह पहली बार हुआ है जब डिजिटल अधिकारों के लिए आधार मूल्य ज्यादा है। बीसीसीआई ने मीडिया अधिकार चक्र के लिए कुल आधार मूल्य को घटाकर 45 करोड़ रुपये प्रति मैच कर दिया है। यह पहली बार हुआ है जब डिजिटल अधिकारों के लिए आधार मूल्य ज्यादा है।

रुप प्रति मैच है। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग टीवी और डिजिटल अधिकारों का आधार मूल्य 49 करोड़ रुपये और 33 करोड़ रुपये प्रति मैच था। कुछ आईपीएल मैचों वाले विशेष डिजिटल अधिकार पैकेज में प्रति मैच 16 करोड़ रुपये का आधार मूल्य रखा गया था। उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि कुछ मीडिया कंपनियों के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, बाजार में सभी प्रमुख खिलाड़ियों की अधिकतम भागीदारी की अनुमति देने के लिए ही आधार मूल्य कम किया गया है। ई-नीलामी 31 अगस्त को शुरू होगी जिसमें डिजनी हॉटस्टार, वायार्काम 18 और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के बीच टीवी और डिजिटल दोनों अधिकारों के लिए प्रतिस्पर्धा होने की उम्मीद है। मीडिया अधिकार निविदा पांच साल (2023-28) के लिए जारी की गई है जिसमें 88 मैच शामिल हैं। प्रति मैच 45 करोड़ रुपये के हिसाब से कुल आधारमूल्य 3,960 करोड़ रुपये आता है। आधार मूल्य कम करते हुए बीसीसीआई ने प्रति मैच 60 करोड़ रुपये या 88 मैचों के लिए 5,280 करोड़ रुपये की सीमा तय की है।

एशिया कप में खेल सकते हैं राहुल

मुंबई । बल्लेबाज लोकेश राहुल आजकल रिहबे के दौर से गुजर रहे हैं। अब तक कहा जा रहा था कि वह पूरी तरह से फिट नहीं हैं और उनका एशिया कप खेलना संदिग्ध है पर अब आईएनएन रिपोर्ट के अनुसार राहुल एशिया कप में खेल सकते हैं। राहुल आईपीएल 2023 में चोट के कारण बाहर हो गए थे। राहुल अगर एशिया कप से पहले वापसी करते हैं तो उनको अपनी लय हासिल करने का अच्छा अवसर भी मिल जाएगा क्योंकि इस बार ये टूर्नामेंट 50 ओवरों का खेला जाएगा। राहुल ने पिछले दिनों स्वयं सोशल मीडिया पर अपनी तैयारी का एक वीडियो भी जारी किया इसमें वे विकेटकीपिंग के साथ-साथ बल्लेबाजी अभ्यास भी करते दिखे। वहीं मध्य क्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा भी चोट के बाद वापसी के लिए तैयार हैं। इन दोनों को ही आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में जगह भी मिली है। एशिया कप के मुकाबले 30 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाने हैं। इसमें कुल 6 टीमों भाग लेंगी। इसमें भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है और दोनों की टक्कर 2 सितंबर को होनी है। राहुल के एकदिवसीय रिकॉर्ड की बात करें, तो उन्होंने अब तक 54 मैच की 52 पारियों में 45 की औसत से 1986 रन बनाये। 112 रन उन सबसे अधिक स्कोर होने के साथ ही स्ट्राइक रेट 87 का है। लिस्ट-ए क्रिकेट में 9 शतक के अलावा 26 अर्धशतक भी उनके नाम हैं। एशिया कप के लिए अगले सप्ताह टीम की घोषणा हो सकती है। इसमें उन्हें खिलाड़ियों को अवसर दिया जाएगा जिन्हें विश्वकप के लिए टीम में शामिल किया जाएगा।



वेस्टइंडीज ने पहले टी20 में भारतीय टीम को चार रनों से हराया

सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की

तरौबा ।

भारतीय क्रिकेट टीम को मेजबान वेस्टइंडीज के हाथों यहां पहले ही टी20 मुकाबले में चार रनों से हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच में मेजबान टीम के कप्तान कप्तान रोबर्ट मैनर पॉवेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम ने निकोल्स पूरन के 41 और कप्तान रोबर्ट मैनर पॉवेल के 48 रनों की सहायता से 20 ओवरों में 149 रन बनाए। इस प्रकार भारतीय टीम को जीत के लिए 150 रनों का लक्ष्य मिला जिसका पीछा करते हुए भारतीय टीम 9 विकेट पर 145 रन ही बना पाई। भारतीय टीम की ओर से युवा तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए। इसके अलावा अर्शदीप सिंह ने भी कुछ अच्छे शॉट

लगाये पर वह टीम को जीत नहीं दिला पाये। इस जीत के साथ ही मेजबान टीम पांच मैचों की इस सीरीज में 1-0 से आगे हो गयी है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम को सलामी बल्लेबाज बैंडन किंग 28 ने तेज शुरूआत दी पर स्पिनर जुवेन्द्र चहल ने किंग और दूसरे सलामी बल्लेबाज काइल मायर्स 01 को पेवेलियन भेज दिया। इसके बाद चहल के साथी कुलदीप यादव ने जॉनसन चार्ल्स को भी तीन रनों पर ही आउट कर दिया। इसके बाद निकोल्स पूरन ने पारी संभाली। पूरन ने 34 गेंदों पर दो चौके और दो छके लगाकर 41 रन बनाए। पूरन को कप्तान हार्दिक पांड्या ने आउट किया। पॉवेल ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाये। अपनी पारी में इस बल्लेबाज ने 32 गेंदों पर 3 चौके और 3 छके लगाकर

48 रन बटोरे। वहीं शिमरोन हेटमायर ने 10 रनों का योगदान दिया। अंत में होल्डर ने स्कोर को 149 तक पहुंचाया। भारत की ओर से अर्शदीप और चहल ने 2-2 विकेट लिए जबकि पांड्या और कुलदीप को 1-1 विकेट मिला। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरूआत कमजोर रही। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 03 और ईशान किशन 05 शुरूआत में ही आउट हो गये। तब सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा ने तेजी से खेलते हुए अच्छे साझेदारी बनायी। सूर्यकुमार यादव 21 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तिलक ने 22 गेंदों पर दो छके लगाकर 39 रन बनाए। वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या 19 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हो गए। बल्लेबाज सजू सैमसन से इस मैच में बड़ी पारी



की उम्मीद थी पर उन्होंने निराश किया। वह 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर बर्दकस्मती ने रन आउट हो गये। सैमसन ने आउट होने के बाद विकेट लगातार गिरने लगे। बाकि के बचे हुए बल्लेबाज दो अंकों तक भी नहीं पहुंच पाये।

तमीन ने बांग्लादेश एकदिवसीय टीम की कप्तानी छोड़ी

ढाका । बांग्लादेश के बल्लेबाज तमीन इकबाल ने हाल में संन्यास की घोषणा से पलटते हुए वापसी की थी। तमीन ने अफगानिस्तान के खिलाफ हार के बाद अचानक ही खेल को अलविदा कह दिया था। वहीं अब बल्लेबाज ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि वह एकदिवसीय टीम की कप्तानी नहीं करेंगे। तमीन ने कहा, मैंने हमेशा पहले टीम के बारे में सोचा है। टीम की भलाई के लिए ही मेरा मानना है कि मुझे कप्तानी छोड़ देनी चाहिए और एक खिलाड़ी के रूप में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही जब भी अवसर मिले अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने अपने फैसले के बारे में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी जानकारी दे दी थी और उन्होंने इसे मान भी लिया है। तमीन ने जुलाई में घरेलू सीरीज के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था पर एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री के अनुरोध पर उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया था। अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के पहले मैच में अपनी टीम की हार के बाद तमीन भावुक हो गये थे। वहीं बीसीबी अध्यक्ष नजमुल हसन ने तमीन के फिट नहीं होने के बाद भी खेलने के लिए आलोचना की थी। वहीं हसीना ने अगले दिन तमीन और नजमुल को अपने आवास पर आमंत्रित किया, जिसके बाद इस क्रिकेटर को संन्यास से वापसी करनी पड़ी।



टीम इंडिया 200 टी20 मैच खेलने वाली दूसरी टीम बनी

तरौबा । भारतीय क्रिकेट टीम ने मेजबान वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 में उतरने के साथ ही एक अहम उपलब्धि अपने नाम कर ली है। इस मैच के साथ ही भारतीय टीम ने अपना 200 वां टी20 मैच खेला है। इस आंकड़े तक पहुंचने वाली वह पहली टीम है। वहीं सबसे अधिक टी20 खेलने का रिकॉर्ड पाकिस्तान टीम के नाम है। उसने अब तक 223 टी20 मैच खेले हैं। न्यूजीलैंड टीम इस सूची में तीसरे नंबर पर है उसके नाम 193 जबकि श्रीलंका और वेस्टइंडीज के नाम 179 मैच हैं। ऑस्ट्रेलिया 174, इंग्लैंड 173, दक्षिण अफ्रीका 168 और बांग्लादेश और आयरलैंड के नाम 152 मैच हैं। इस मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान रोबर्ट मैनर पॉवेल ने टॉस जीत पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैच में मेजबान टीम को चार रनों से जीत मिली। वहीं भारतीय टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या ने की।



एसकेएम पार्टी महिलाओं के प्रति उदार नहीं : जूडी राई



अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 04 अगस्त। राज्य मंत्रिमंडल में किसी महिला को जगह नहीं देने पर एसडीएफ पार्टी की प्रचार प्रसार महासचिव जूडी राई ने एसकेएम सरकार पर निशाना साधा है।

यहाँ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में श्रीमती राई ने कहा कि लगभग छह महीने के बाद आखिरकार सिक्किम सरकार के स्वास्थ्य विभाग में एक स्वास्थ्य मंत्री को मनोनीत किया गया है। स्वास्थ्य विभाग जैसे प्रमुख विभाग पिछले छह महीने से बिना मंत्री के चल रहे थे। सिक्किम के इतिहास में यह पहली और नई घटना है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एसकेएम सरकार अब तक कई बार अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर चुकी है। हालाँकि, कैबिनेट फेरबदल के बावजूद, एसकेएम सरकार महिला विधायकों को मंत्री के रूप में शामिल नहीं कर सकी। विधानसभा में तीन महिला विधायकों के रहते हुए भी महिला विधायकों की उपेक्षा और मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में भी महिलाओं की भागीदारी और सामाजिक न्याय को कमजोर कर वह एक और इतिहास रचने में सफल रही है।

श्रीमती राई ने कहा कि गंगटोक नगर पालिका के मेयर पद के लिए आधा-आधा का फार्मूला तैयार कर महिला प्रत्याशियों की उपेक्षा करने का ऐतिहासिक कृत्य कोई नहीं भूल सकता। एसडीएफ पार्टी चेली मोर्चा का मानना है कि इससे साबित होता है कि महिलाओं की रक्षक होने का

एसकेएम सरकार का दावा केवल प्रचार है।

उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा में फिलहाल तीन महिला विधायक हैं। श्रीमती सुनीता गजमेर, जो एसकेएम पार्टी की विधायक हैं, श्रीमती राजकुमारी थापा और श्रीमती परवती तमांग भाजपा विधायक हैं। जनमत से निर्वाचित होकर विधायक बनीं तीन महिला विधायक प्रदेश की संपूर्ण महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, भले ही वे किसी भी पार्टी से हों। इसलिए, अगर एसकेएम सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल में एक महिला विधायक को मंत्री बनाया होता, तो यह पूरी सिक्किम महिला जाति को सम्मान देना होता। लेकिन एसकेएम पार्टी महिलाओं के प्रति उदार नहीं है।

उन्होंने कहा कि एसडीएफ पार्टी सामाजिक न्याय के खिलाफ एसकेएम सरकार के ऐतिहासिक कार्यों की निंदा करती है और महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए हमेशा दृढ़ रहने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करती है। बहरहाल, लंबे समय से मंत्री विहीन रहे स्वास्थ्य विभाग में नवनियुक्त मंत्री श्री बिष्णु प्रसाद खतिवड़ा में हार्दिक बधाई देती हैं और उनके सफल प्रदर्शन की कामना करती हैं। उन्होंने कहा कि चूँकि चुनाव में काफी कम समय हैं इतने कम समय में खराब स्थिति से गुजर रहे स्वास्थ्य विभाग को संभालना उनके लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। एसडीएफ पार्टी चाहती है कि शक्ति ईश्वर उन्हें इस विभाग को अच्छे से संभालने की ताकत दें।

ट्यूबवेल पर बिजली बिल लगाने की आप- कांग्रेस की साजिश को सफल नहीं होने देंगे: बादल

फरीदकोट (पंजाब), 04 जुलाई (एजेन्सी)। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने शुक्रवार को कहा कि शिअद ट्यूबवेल कनेक्शन पर बिजली बिल लगाने की आप- कांग्रेस की साजिश को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। शिअद के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने चेतावनी दी कि वे किसानों के साथ भेदभाव करने की कोशिश न करें। किसान पहले से ही आप सरकार की मानव निर्मित बाढ़ के कारण हुए विनाश से जूझ रहे हैं।

फरीदकोट में मीडिया को संबोधित करते हुए शिअद अध्यक्ष बादल ने कहा कि अब जब आप- कांग्रेस राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक साथ हो गए हैं, तो उन्हें लगता है कि वे अपनी इच्छानुसार कोई भी निर्णय ले सकते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह

बादल द्वारा किसानों को दी गई मुफ्त बिजली सब्सिडी में अकाली दल कोई कमी नहीं आने देगा। अगर इस सब्सिडी के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गई तो हम आंदोलन शुरू करेंगे। बादल ने कहा कि किसानों को निशाना बनाने की आप- कांग्रेस की संयुक्त साजिश विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा शुरू की गई थी, जिसके अध्यक्ष कांग्रेसी तुष राजिंदर सिंह बाजवा थे और इसमें कई आप विधायक शामिल थे।

आप सरकार किसी न किसी बहाने किसानों को मिल रही मुफ्त बिजली फैसेलिटी वापस लेना चाहता है। उसने राज्य के वित्त का दुरुपयोग किया है और पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को उचित सब्सिडी देने में असमर्थ है। नए बिजली अधिनियम में पीएसपीसीएल को सब्सिडी राशि



अग्रिम रूप से देना अनिवार्य कर आप सरकार ने मुफ्त बिजली सब्सिडी को पूरी तरह खत्म करने की साजिश में कांग्रेस को शामिल कर लिया है।

आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में पूछे जाने पर बादल ने कहा, 'अकाली दल आप- कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। हम सभी प्रमुख कस्बों और शहरों में सभी विकास कार्यों के पूरी तरह से रुकने के साथ-साथ बुनियादी सेवाओं को बनाए

रखने में भी आप सरकार की विफलता को उजागर करेंगे।

सभी कस्बे और शहर पीड़ित हैं क्योंकि आप सरकार विज्ञापनों पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च कर रही है और देश भर में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के पदचिह्न का विस्तार कर रही है। हम इस फिजूलखर्ची को रोकने की मांग करेंगे। इसके अलावा हम मांग करेंगे कि कस्बों और शहरों के विकास के लिए उचित धन आवंटित किया जाए।

हरित हाइड्रोजन में निवेश की तलाश में दक्षिण कोरिया पहुंचा सिक्किम का प्रतिनिधिमंडल



आईपीआर

गंगटोक, 04 अगस्त। दक्षिण कोरिया से हरित हाइड्रोजन निवेश संभावनाओं की तलाश हेतु सिक्किम के वाणिज्य व उद्योग सचिव कर्मा आर बोनोपो के नेतृत्व में राज्य के एक प्रतिनिधिमंडल ने वहाँ का दौरा किया।

इस दौरान सिक्किमी प्रतिनिधिमंडल ने इंडिया-पैसिफिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पार्टनरशिप सेंटर, कोरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट के प्रबंध निदेशक जो जिन चेओल, योशिन इजीनियरिंग कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष कांग ताए चूपाक, जेएनके हीटर कंपनी लिमिटेड के जोंग हान और विनटेक कंपनी

लिमिटेड के सीओओ ग्येंग चुल किम के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के साथ नवीकरणीय नगरों के विकास को लेकर बैठक की।

वहीं, इस यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सियोल में एक भूमि भराव स्थल से उत्पन्न मीथेन से हाइड्रोजन का उत्पादन करने एक हाइड्रोजन स्टेशन का भी दौरा किया। बताया गया कि इस स्टेशन की हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 600 किलोग्राम की है और इसे जेएनके हीटर कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है।

गौरतलब है कि सिक्किम सरकार राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर एक हाइड्रोजन हब बनाने के लिए तत्पर है और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए राज्य की जल

ऊर्जा का उपयोग करने की योजना बना रही है। इस ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग परिवहन, भवन और आवास आवश्यकताओं और विभिन्न उद्योगों के लिए किया जा सकता है। यह मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में राज्य सरकार के भावी दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य को देश के हरित निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करना है। जानकारी के अनुसार, सिक्किम में देश में हरित हाइड्रोजन ईको सिस्टम विकास का संचालन करने वाले अग्रणी राज्यों में शुमार होने की क्षमता है। इस क्षेत्र से राज्य में लगभग 25000 नौकरियाँ पैदा होने के साथ उद्यमिता और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।

इससे पहले, सिक्किम ने इस

क्षेत्र के साथ काम करने के लिए योजना आयोग की एक स्वायत्त संस्था के स्ट्रक्चर इंज इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट कार्डिनल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसी कड़ी में अब कोरिया की पर्यावरण, क्षेत्रीय व शहरी विकास, बुनियादी ढांचे, भूमि उपयोग, परिवहन व भौगोलिक सूचना प्रणाली आदि क्षेत्रों में शोध कार्य करने वाली कोरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट भी कोरियाई कंपनियों की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ इस क्षेत्र में काम करने के लिए सिक्किम के साथ साझेदारी करने और राज्य में हाइड्रोजन स्मार्ट सिटी के संचालन हेतु ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस का लाभ उठाने के लिए उत्सुक है।

मानहानि केस में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सजा पर रोक

नई दिल्ली, 04 अगस्त (एजेन्सी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में बड़ी बात यह भी यह थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, कोर्ट की टिप्पणी के अलावा ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया। यदि सजा एक दिन भी कम होती तो अयोग्यता से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होता। ट्रायल जज से कम से कम यह अपेक्षा की जाती है कि वह गैर संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम सजा देने के कारण बताएँ। हालाँकि, अपीलीय अदालत और हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने में काफी पने खर्च किए हैं, लेकिन इन पहलुओं पर ध्यान नहीं

दिया गया है। ऐसे मामलों में सार्वजनिक व्यक्ति से कुछ हद तक सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।

आदेश के मुताबिक, ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ। इन बातों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से यह कि ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है जिससे अयोग्यता हुई है, कार्यवाही के लंबित रहने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। अपील के लंबित रहने से अपीलीय अदालत को कानून के अनुसार निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे मूड में नहीं होते हैं। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। कोर्ट ने अवमानना याचिका में राहुल के हलफनामे को रवीकार करते हुए कहा कि उन्हें अधिक सावधान रहना चाहिए था।

इससे पहले राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि उन्हें सजा पर रोक के लिए आज एक असाधारण मामला बनाना होगा। राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम 'मोदी' नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया। राहुल ने अपने भाषण के दौरान जिन लोगों का नाम लिया था, उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया। यह 13 करोड़ लोगों का एक छोट सा समुदाय है और इसमें कोई एकरूपता या समानता नहीं है। सिंघवी ने कहा कि इस समुदाय में केवल वही लोग पीड़ित हैं जो भाजपा के पदाधिकारी हैं और मुकदमा कर रहे हैं।

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जज इसे नैतिक अधमता से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हैं। यह गैर-संज्ञेय और कि अधिकतम सजा क्यों दी गई? कोर्ट का मानना है कि अगर जज ने एक साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी अयोग्य नहीं उठराए जाते।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात

कोई कट्टर अपराधी नहीं हैं। राहुल गांधी पहले ही संसद के दो सत्रों से दूर रह चुके हैं।

'मोदी सरनेम' टिप्पणी मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेटमलानी ने तर्क दिया कि पूरा भाषण 50 मिनट से अधिक समय का था और भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भाषण के टेरे सारे सबूत और क्लिपिंग संलग्न हैं। जेटमलानी का कहना है कि राहुल गांधी ने टिप्पणी एक पूरे वर्ग को बदनाम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राहुल गांधी को आगाह किया था, जब उन्होंने कहा था कि राफेल मामले में शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि उनके आचरण में कोई बदलाव नहीं आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला काफी दिलचस्प है। राहुल गांधी की सजा कम भी हो सकती थी। वह जानना चाहता है कि अधिकतम सजा क्यों दी गई? कोर्ट का मानना है कि अगर जज ने एक साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी अयोग्य नहीं उठराए जाते।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात

के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि इस स्तर पर सीमित प्रश्न यह है कि क्या दोषसिद्धि निर्लंबित किए जाने योग्य है? पूर्णेश मोदी और राहुल गांधी ने कोर्ट के समक्ष अपने-अपने जवाब दाखिल कर दिए थे।

2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रेली में राहुल गांधी ने कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?' इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

23 मार्च को निचली अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। राहुल की अपना सरकारी घर भी खाली करना पड़ा था। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ दो अप्रैल को राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने



से इनकार कर दिया था। इसके बाद सात जुलाई को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और राहुल की याचिका खारिज कर दी थी।

गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि राजनीति में शुचितता अब समय की मांग है। जनप्रतिनिधियों को साफ छवि का होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि दोषसिद्धि पर रोक लगाना नियम नहीं, बल्कि अपवाद है। इसे विरले मामलों में ही इस्तेमाल किया जाता है। जस्टिस प्रच्छक ने 125 पेज के अपने फैसले में कहा था कि राहुल गांधी पहले ही देशभर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में निचली अदालत का आदेश न्यायसंगत, उचित और वैध है।

पर्यटक टैक्सी चालकों के लिए कार्यशाला आयोजित



अनुगामिनी नि.सं.

नामची, 04 अगस्त। सिक्किम सरकार के पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के गुवाहाटी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय के साथ आज गेंजिंग, सोरेंग और नामची में पर्यटक टैक्सी चालकों के लिए शिष्टाचार और साज-सज्जा पर केंद्रित कार्यशालाओं का आयोजन किया।

वहीं, मंगल, गंगटोक और पाकिम जिलों में भी ऐसी कार्यशालाएँ होनी बाकी हैं। बताया गया है कि इन कार्यशालाओं का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में आने वाले पर्यटक टैक्सी चालकों की व्यावसायिकता और सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ ही उनको शिष्टाचार, साज-सज्जा के महत्व और पर्यटकों के समग्र अनुभव को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूक बनाना था।

कार्यशालाओं के दौरान, सिक्किम के विभिन्न विभागों के रिसोर्स पर्सनॉल ने टैक्सी चालकों के साथ बातचीत की और सड़क चिकित्सा आपात स्थिति से निपटने, मोटर वाहन नियमों का पालन करने, सिक्किम की जैव विविधता को समझने और विभिन्न पर्यटन स्थलों का ज्ञान प्रदान करने के बारे में जानकारी प्रदान की। इसके अलावा, उन्होंने प्रभावी शिष्टाचार और साज-सज्जा के माध्यम से ग्राहकों-मुझे दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया।

इन कार्यशालाओं ने निर्बाध और समुचित पर्यटन अनुभव सुनिश्चित करने हेतु परिवहन, स्वास्थ्य, पुलिस, स्थानीय समुदायों, आतिथ्य उद्योग और पर्यावरण एजेंसियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। टैक्सी चालकों को राज्य की संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

कार्यक्रम में तकनीकी सत्रों के दौरान पर्यटन व नागरिक उड्डयन

विभाग के रिसोर्स पर्सन सोनम रिचचेन भूटिया, उपनिदेशक लामिन थेंग एवं दीप्ति राई, नामची टीओ दीपा गुरुंग ने पर्यटक टैक्सी चालकों के पेशे के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए वक्तव्य रखे। इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं नामची जिला मोटर वाहन कार्यालय से डॉ. कंचन गुरुंग ने सड़क पर लगने वाली चोटों, उनकी चिकित्सा और आपात स्थितियों से निपटने पर जानकारी दी।

वहीं, एएमवीआई दर्जी वांगेल भूटिया और जिला मोटर वाहन कार्यालय से एएमवीआई इस्माइल मंगर ने मोटर वाहन नियमों और विनियमों के बारे में बताया। इसके अलावा, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-ईडिया का लैंडस्केप समन्वयक लक्सशेडेन थॉंग ने सिक्किम की जैव विविधता और इसके महत्व पर प्रस्तुति दी। उन्होंने राज्य की लुप्तप्राय प्रजातियों पर प्रकाश डालते हुए इसके कारणों को स्पष्ट करते हुए उनके संरक्षण हेतु रूपरेखा तैयार की।

इस दौरान, नामची पर्यटक सूचना केंद्र की उपनिदेशक लामिन थेंग ने सिक्किम में पर्यटन के विभिन्न पहलुओं पर जोर देते हुए पर्यटकों के साथ प्रभावी संचार सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय भाषा में दक्षता सहित बहुभाषी कौशल रखने के महत्व को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने टैक्सी चालकों और पर्यटन उद्योग में शामिल लोगों के बीच पेशेवर शिष्टाचार और सौंदर्य

डियर साप्ताहिक लॉटरी
दक्षिण दिनाजपुर निवासी ने
₹ 1 करोड़ जीते

लॉटरी के ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार के तौर पर ₹. 1 करोड़ जीते हैं। उनकी विजेता टिकट का नंबर **3 9 A 77638** है। उन्होंने कोलकाता स्थित नागालैंड स्टेट लॉटरीज के नोडल अधिकारी के पास प्राइज क्लेम फॉर्म के साथ अपनी पुरस्कार-विजेता टिकट जमा कर दी है। 'मैं नहीं जानता कि अब अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करूं? केवल कुछ रूपरेखा के निवेश से एक करोड़ रूपरेखा जीतना पूरी तरह अद्भुत है। डियर लॉटरी तथा नागालैंड स्टेट लॉटरीज के प्रति मेरा सम्पूर्ण आभार। मेरे द्वारा जीती गई पुरस्कार राशि से अब मेरा जीवन सुचारु रूप से चलगा।' विजेता ने कहा। डियर लॉटरी के ड्रॉ लाइव दिखाए जाते हैं।

दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल के श्री संजय हरिजन ने **09.06.2023** को सम्पन्न हुए डियर साप्ताहिक